भारतीय वैश्विक परिषद

सप्रू हाउस शोधपत्र

भारत- दक्षिण कोरिया रणनीतिक साझेदारी- नए स्तर की ओर

डॉ. जोजिन वी. जॉन

अध्येता (रिसर्च फेलो)

भारत- दक्षिण कोरिया रणनीतिक साझेदारी

नए स्तर की ओर

प्रथम प्रकाशन, 2022

कॉपीराइट © भारतीय वैश्विक परिषद

आईएसबीएनः 978-93-83445-63-9

सर्वाधिकार सुरक्षित। कॉपीराइट मालिक की लिखित अनुमति के बिना इस प्रकाशित पुस्तक के किसी भी हिस्से को किसी भी रूप में या किसी भी माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक, यांत्रिक, फोटोकॉपी रिकॉर्डिंग या अन्यथा, पुनः प्रस्तुत, एक पुनर्प्राप्ति प्रणाली में संग्रहीत या प्रेषित नहीं किया जा सकता है।

इस प्रकाशित पुस्तक में तथ्यों एवं विचारों का उत्तरदायित्व विशेष रूप से लेखक का है और उनकी व्याख्या आवश्यक रूप से भारतीय वैश्विक परिषद, नई दिल्ली के विचारों या नीति को प्रतिबिंबित नहीं करता है।

भारतीय वैश्विक परिषद

सप्रू हाउस, बाराखंभा रोड,

नई दिल्ली- 110001, भारत

दूरभाषः +91-11-23317242, फैक्सः +91-11-23322710

www.icwa.in

द्वारा मुद्रित

अल्फा ग्राफिक्स

6ए/1, गंगा चैम्बर्स, डब्ल्यू.ई.ए.,

करोल बाग, नई दिल्ली- 110005

दूरभाषः 9312430311

ईमेलः tarunberi2000@gmail.com

विषयवस्तु

1. परिचय 7
2. (पुनः) खोज का युगः शीतोत्तर काल में भारत- कोरिया संबंध 9
3. रणनीतिक साझेदार बनानाः समेकन काल 15
4. विशेष रणनीतिक साझेदारी के माध्यम से संबंधों में मजबूत बनाना 24
5. रणनीतिक साझेदारी प्रतिमान के तहत द्विपक्षीय संबंधों में विकास 31
6. हिंद- प्रशांत और भारत-कोरिया संबंधों का भविष्य 55
7. निष्कर्ष 65

भारत- दक्षिण कोरिया रणनीतिक साझेदारी

नए स्तर की ओर

सारांश

बीते दो दशकों में भारत-दक्षिण कोरिया (कोरिया) के संबंधों में उत्तरोत्तर प्रगति हुई है। वर्ष 2010 में हुआ रणनीतिक साझेदारी समझौता और 2015 में विशेष रणनीतिक साझेदारी समझौता, संबंधों में सुधार की दो प्रमुख घटनाएं रही हैं। रणनीतिक साझेदारी के लिए द्विपक्षीय संबंधों की स्थिति में सुधार दोनों देशों द्वार संबंधों को दिए जाने वाले प्राथमिकता को दर्शाते हैं और अंतरराष्ट्रीय मामलों में महत्वपूर्ण देशों के रूप में एक दूसरे के उभरने की पारस्परिक मान्यता का प्रतीक हैं। घरेलू कारकों के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय संबंधों का संरचनात्मक आयाम द्विपक्षीय संबंधों को आकार देने में महत्वपूर्ण कारक रहा है।

शीत युद्ध के बाद के युग के वैश्वीकरण और क्षेत्रीय एकीकरण की अनुकूल अंतरराष्ट्रीय और क्षेत्रीय व्यवस्था ने संस्थागत संबंध स्थापित करने में मदद की और एक भावात्मक रूपरेखा प्रदान की जो दोनों देशों को करीब लेकर आया। हालांकि, संरचनात्मक परिवर्तन की प्रक्रिया, 2008 के वित्तीय संकट के बाद के काल में पुनर्संतुलन और विवैश्वीकरण द्वारा संवर्धित और कोविड-19 महामारी द्वारा प्रेरित भू-राजनीतिक तनाव और विकसित देशों में प्रतिद्वंद्विता, द्विपक्षीय संबंधों को चुनौती देती है। संरचनात्मक एवं द्विपक्षीय कारकों और इतिहास, संस्थागत और क्षेत्रीय विकास के मानचित्रण के संदर्भ में, यह शोधपत्र 'रणनीतिक साझेदारी' प्रतिमान के तहत भारत-कोरिया संबंधों का व्यापक विश्लेषण प्रस्तुत करता है। आखिर में, यह देखा गया है कि महत्वपूर्ण द्विपक्षीय हित होने के बावजूद, क्षेत्रीय व्यवस्था परिवर्तन में हाल के घटनाक्रमों में, यदि धारणा और अपेक्षाओं के अंतराल पर पर्याप्त ध्यान न दिया जाए तो इसमें संबंधों की गतिशीलता को कमजोर बनाने की क्षमता है।

1. परिचय

भारत-दक्षिण कोरिया (कोरिया) के संबंधों में बीते दो दशकों में उत्तरोत्तर प्रगति हुई है। वर्ष 2004 में 'शांति एवं समृद्धि हेतु दीर्घकालिक सहयोगी साझेदारी' से लेकर 2010 में 'रणनीतिक साझेदारी' और 2010 में 'विशेष रणनीतिक साझेदारी' के लिए द्विपक्षीय संबंधों की स्थिति में सुधार दोनों देशों के संबंधों में निरंतर प्रगति को दर्शाता है। द्विपक्षीय संबंधों की स्थिति का समय-समय पर उत्थान राजनीतिक अनिवार्यता को दर्शाते हुए ऐतिहासिक परिवर्तन को भी दर्शाता है। हालांकि, इसके साथ संबंधों में स्वरूप एवं वास्तविकता में भी सुधार हुआ है।

शीत युद्ध के बाद की अवधि में आर्थिक संबंधों पर केंद्रित छोटे प्रयास से शुरू होकर भारत- कोरिया संबंधों ने व्यापक और बहुआयामी साझेदारी का लंबा सफर तय किया है। वर्ष 2009 में एक व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते (सीईपीए) पर हस्ताक्षर करने के साथ आर्थिक साझेदारी द्विपक्षीय संबंधों का मजबूत स्तंभ बनी हुई है, रक्षा एवं सुरक्षा, विकास साझेदारी, अंतरिक्ष, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, क्षेत्रीय मुद्दे, परमाणु ऊर्जा, समुद्री सहयोग जैसे अन्य क्षेत्रों को शामिल करने के लिए इसका दायरा काफी बढ़ाया गया है। इसके अलावा, वास्तविकता के साथ- साथ संबंधों के स्वरूप में भी बहुत सुधार हुआ है। यह आयाम लगातार उच्च-स्तरीय द्विपक्षीय आदान-प्रदान और विभिन्न स्तरों पर संस्थागत संवाद तंत्र के माध्यम से दोनों देशों के बीच राजनीतिक संबंधों की गहनता में परिलक्षित हुआ है। इसके अलावा, हाल के वर्षों में सांस्कृतिक एवं लोगों के बीच आपसी बातचीत के साथ संबंधों की जागरूकता और लक्ष्यता में सुधार हुआ है।

नीति और अकादमिक चर्चाओं में संबंधों में विकास पर भी ध्यान दिया गया है। हालांकि, रणनीतिक साझेदारी प्रतिमान के तहत भारत-कोरिया द्विपक्षीय संबंधों का व्यापक विश्लेषण करने के लिए सीमित प्रयास किए गए हैं।[1] शोधपत्र इतिहास, संस्थागत और वास्तविकता पर ध्यान केंद्रित करते हुए दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी की विकासवादी कहानी को बताने का एक प्रयास है। वर्तमान मुद्रित सामग्री में एक और कमी यह है कि इसमें संरचनात्मक कारकों पर सीमित ध्यान दिया गया है, जैसे, द्विपक्षीय संबंधों में सुधार में सत्ता के बदलते वैश्विक और क्षेत्रीय संतुलन की भूमिका। शीत युद्ध के बाद की अवधि के अनुकूल अंतरराष्ट्रीय आदेश - वैश्वीकरण और क्षेत्रीय एकीकरण की विशेषता- ने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने हेतु अनुकूल माहौल प्रदान किया। हालांकि पिछले दशकों में यह निष्क्रिय दिखाई दिया, लेकिन हाल के वर्षों में अंतरराष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय कारकों की भूमिका अधिक स्पष्ट हुई है। वर्ष 2008 के वित्तीय संकट के बाद की अवधि में पुनर्संतुलन और वि-वैश्वीकरण की प्रक्रियाओं द्वारा संवर्धित संरचनात्मक परिवर्तन की घटनाएं और कोविड-19 महामारी द्वारा त्वरित, बढ़े हुए भू-राजनीतिक तनाव और सत्ता प्रतिद्वंद्विता द्विपक्षीय संबंधों के लिए चुनौती पेश करती है। विकासशील अंतरराष्ट्रीय संदर्भ में भारत-कोरिया संबंधों पर विचार करते हुए, शोधपत्र में यह तर्क दिया गया है कि यदि धारणा और अपेक्षाओं के अंतराल पर पर्याप्त ध्यान न दिया जाए तो महत्वपूर्ण द्विपक्षीय हित होने के बावजूद, क्षेत्रीय व्यवस्था परिवर्तन में विकास संबंधों की गतिशीलता को कमजोर कर सकता है।

शोधपत्र सात विषयगत वर्गों में लिखा गया है। परिचय के बाद दूसरा खंड, भारत-कोरिया संबंधों की संक्षिप्त पृष्ठभूमि का है। तीसरा खंड 2010 में रणनीतिक साझेदारी के निर्माण हेतु प्रमुख संदर्भों और कारकों का मूल्यांकन करता है। विशेष रणनीतिक साझेदारी के तहत द्विपक्षीय संबंधों में महत्वपूर्ण विकास का मूल्यांकन चौथे खंड में किया गया है। पांचवां खंड रक्षा, आर्थिक संबंधों, विज्ञान और प्रौद्योगिकी एवं संस्कृति और लोगों के बीच संपर्क के क्षेत्र में रणनीतिक साझेदारी के प्रतिमान के तहत भारत-कोरिया संबंधों में विकास का विस्तृत अनुभवजन्य विवरण प्रदान करता है। छठा खंड

हिन्द- प्रशांत के उभरते क्षेत्रीय संदर्भ में भारत-कोरिया संबंधों को प्रासंगिक बनाने का प्रयास करता है। अंत में, रणनीतिक साझेदारी के तहत भारत-कोरिया संबंधों के महत्वपूर्ण पहलुओं और इसकी भविष्य की दिशा को उजागर करने वाले सारांश पर समापन खंड में चर्चा की गई है।

2. (पुनः) खोज का युगः शीतोत्तर काल में भारत- कोरिया संबंध

कोरियाई युद्ध के संदर्भ में कोरियाई प्रायद्वीप में नई दिल्ली की वचनबद्धता के साथ भारत और कोरिया के बीच आधुनिक संबंधों की शुरूआत हुई। कोरिया में युद्ध आरंभ होने से भी पहले, जब पहली बार 1947 में कोरिया के मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र (यूएन) में भेजा गया था, कोरियाई प्रायद्वीप का मुद्दा स्वतंत्र भारत का पहला प्रमुख अंतरराष्ट्रीय मुद्दा बन चुका था। नई दिल्ली ने कोरिया पर संयुक्त राष्ट्र के अस्थायी आयोग (यूएनटीसीओके), संयुक्त राष्ट्र द्वारा कोरियाई प्रायद्वीप में 1948 में होने वाले आम चुनावों के पर्यवेक्षण के लिए बनाए गए अंतरराष्ट्रीय निकाय की अध्यक्षता की थी। इस तथ्य को ध्यान में रखना महत्वपूर्ण है कि भारत ने 1948 में दक्षिण कोरिया या उत्तर कोरिया में बनी सरकार को मान्यता देने से इनकार कर दिया था क्योंकि नई दिल्ली का मानना था कि यह विभाजन कृत्रिम था और सरकार को मान्यता देने के बाद विभाजन को भी मान्यता मिल जाएगी।[2] वर्ष 1950 में कोरियाई युद्ध के आरंभ होने के बाद, नई दिल्ली ने संयुक्त राष्ट्र में सक्रिए राजनयिक जुड़ाव के माध्यम से संघर्ष को रोकने का प्रयास किया था।[3] इसने पश्चिम और सोवियत संघ के बीच मध्यस्थता करने का भी प्रयास किया। नई दिल्ली ने कोरियाई युद्ध के दौरान मानवीय प्रयासों में मदद के लिए चिकित्सा मिशन को भी भेजा था। इसके अलावा, नई दिल्ली ने तटस्थ राष्ट्र प्रत्यावर्तन आयोग की अध्यक्षता कर शांति स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जिसे युद्ध के कैदियों (पीओडब्ल्यू) के प्रत्यावर्तन के जटिल मुद्दे को हल करने का काम सौंपा गया था और भारत के संरक्षक बल को कोरियाई प्रायद्वीप में प्रत्यावर्तन प्रक्रिया की व्यवस्था करने हेतु भेजा गया था।[4]

कोरियाई प्रायद्वीप में भारत के कार्यों के बावजूद, भारत और कोरिया के बीच के संबंध न केवल अविकसित रहे बल्कि 1950 के दशक के दौरान दोनों देश एक दूसरे के विरोधी बने रहे। नई दिल्ली के साथ सियोल के अमित्रतापूर्ण रवैया का मुख्य कारण कोरिया के नेता थे, विशेषरूप से राष्ट्रपति सिन्गमैन रई का भारत को समाजवादी गुट का करीबी सहयोगी मानना।[5] कोरिया की गलत धारणा के विपरीत कोरियाई प्रायद्वीप के लिए भारत के दृष्टिकोण को इसकी गुटनिरपेक्ष विदेश नीति द्वारा सूचित किया गया था और नई दिल्ली ने शीत युद्ध की अवधि में प्योंगयांग और सियोल के साथ अपने संबंधों में एक संतुलित दृष्टिकोण बनाए रखा। नई दिल्ली ने 1960 के दशक के आरंभ में दोनों कोरिया के साथ कान्स्युलर संबंध स्थापित किए और 1973 में पूर्ण राजनयिक संबंध बने। राजनयिक संबंधों की स्थापना ने संबंधों को बेहतर बनाने में कुछ विशेष योगदान नहीं दिया। शीत युद्ध प्रतिद्वंद्विता की गहनता और अंतरराष्ट्रीय मामलों में उनकी अपेक्षाकृत कम अहमियत ने दोनों देशों को अपने संबंधित विदेश नीति में दूसरे पर ध्यान नहीं देने दिया। इसके अलावा, शीत युद्ध के दौरान दोनों देशों द्वारा अपनाए गए आर्थिक विकास के अलग- अलग मॉडल भारत की आयात प्रतिस्थापन नीति और कोरिया के निर्यात- आधारित विकास मॉडल थे- ने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूती प्रदान की।[6]

1990 के दशक में, भारत- कोरिया संबंधों ने गति पकड़ी। भारत और कोरिया को करीब लाने वाले माहौल को तीन संरचनात्मक सम्मिलन द्वारा समझाया जा सकता है। पहला, शीत युद्ध का वैचारिक ढांचा, जिसने नई दिल्ली और सियोल को पिछले चार दशकों में करीब आने से दूर रखा, सोवियत संघ

के पतन के साथ बिखर गया। दूसरा, 1991 में भारतीय अर्थव्यवस्था के खुलने से उस संरचनात्मक दीवार को ढहा दिया गया जिसने पिछले दशकों में भारतीय और कोरियाई अर्थव्यवस्थाओं की बातचीत को संभव नहीं होने दिया। तीसरा, विदेश नीति अभिसरण, भारत द्वारा 1991 के बाद अपनाई गई लुक ईस्ट पॉलिसी (एलईपी) ने कोरिया के सेगयेहवा विदेश नीति को पूरक बनाया, जिसका उद्देश्य नई दिल्ली और सियोल को करीब लाने में सियोल की अंतरराष्ट्रीय पहुंच को बढ़ाना था।

वर्ष 1993 में प्रधानमंत्री (पीएम) पी.वी. नरसिम्हा राव की कोरिया यात्रा एक महत्वपूर्ण घटना थी जिसने द्विपक्षीय संबंधों के विकास हेतु बहुत आवश्यक राजनीतिक अवसर प्रदान किए। यह किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री का कोरिया का पहला दौरा था। प्रधानमंत्री राव के दौरे का फोकस भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के संदर्भ में उभर रहे नए अवसरों को सामने रख कर भारत में कोरियाई निवेश को आकर्षित करना था। कोरिया के उदय को स्वीकार करते हुए और द्विपक्षीय संबंधों के महत्व पर प्रकाश डालते हुए प्रधानमंत्री राव ने कहा,

"जिस प्रकार कोरिया गणराज्य एक सशक्त और जीवंत अर्थव्यवस्था के निर्माण के साथ- साथ उत्तर-पूर्व एशिया में शांति और सुरक्षा के पक्ष में अपनी स्वतंत्र नीतियों को मजबूत बनाने के लिए गतिशील, अन्य देशों के लिए पहले से अधिक अवसर वाली (आउटवार्ड- लुकिंग) विदेश नीति का अनुसरण कर रहा है, हम इसकी सराहना करते हैं। बदलती अंतरराष्ट्रीय स्थिति के लिए हमारे नजरिए और दृष्टिकोण के सामान्य तत्व, विशेष रूप से एशिया में, भारत और कोरिया गणराज्य को पारस्परिक लाभ के लिए मिल कर काम करने...नए अवसरों, जो पैदा हो रहे हैं (भारत में) का लाभ उठाने के लिए के अनेक अवसर प्रदान करते हैं। हम भारत आने और इस प्रक्रिया में भाग लेने के लिए अधिक- से- अधिक कोरियाई व्यवसायों का स्वागत करेंगे।"[7]

आगे चलकर, विदेश मंत्री और बाद में भारत के राष्ट्रपति बने प्रणब मुखर्जी ने 2007 में प्रधानमंत्री राव के इस दौरे के महत्व को बताया और जिसमें भारतीय नेताओं द्वारा नई दिल्ली के साथ सियोल के संबंधों को प्राथमिकता देने की बात को रेखांकित किया। उन्होंने कहा,

"जैसा कि अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था इस महत्वपूर्ण संरचनात्मक परिवर्तन की गवाह है, हम परिवर्तन लाने और अपनी बाहरी प्राथमिकताओं में सुधार की प्रक्रिया में लगे हुए हैं। यह तब शुरू हुआ जब भारत ने 1990 के दशक की शुरूआत में "लुक ईस्ट पॉलिसी/ पूर्व की ओर देखो नीति" अपनाई। वह मौलिक नया कदम केवल अर्थशास्त्र का परिणाम ही नहीं था; यह 21वीं सदी में विश्व के प्रति भारत के नजरिए में रणनीतिक बदलाव भी था। हम अपने पूर्व में रहने वाले पड़ोसी देशों की उपलब्धियों के बारे में जानते थे जिन्होंने आर्थिक महाशक्तियों के रूप में उभरकर हमें यह संदेश भी दिया कि उद्यम को समृद्ध बनाने से आर्थिक विकास में तेजी आती है। उपलब्धि हासिल करने वालों में कोरिया गणराज्य सबसे आगे है और 1993 में किसी भारतीय प्रधानमंत्री का पहला दौरा कोई संयोग नहीं था।"[8]

प्रधानमंत्री राव और वित्त मंत्री एवं भविष्य में भारत के प्रधानमंत्री बने मनमोहन सिंह समेत कई भारतीय नेताओं ने पूर्वी एशिया के उल्लेखनीय आर्थिक परिवर्तन पर ध्यान दिया, विशेष रूप से जापान और कोरिया में एवं भारत के आर्थिक सुधार के कठिन कार्य को पूरा करने के दौरान भारत के नेताओं को बहुत प्रभावित किया।[9] भारत के पूर्व विदेश सचिव सलमान हैदर ने यहां तक दावा किया है कि प्रधानमंत्री राव के कोरिया दौरे ने भारत के एलईपी की शुरूआत की संभव बनाया।[10]

वर्ष 1996 में कोरियाई राष्ट्रपति किम यंग- सैम की भारत की राजकीय यात्रा ने द्विपक्षीय संबंधों को और बढ़ावा दिया। यह किसी कोरियाई राष्ट्रपति की पहली भारत यात्रा थी। राष्ट्रपति किम की यात्रा का फोकस, "दोनों देशों के बीच सहयोगात्मक संबंध को साझेदारी के उच्च स्तर तक ले जाना और नए

प्रशांत एवं हिन्द महासागर क्षेत्रों की संयुक्त समृद्धि" पर था। इस संबंध में, उन्होंने तीन विचार प्रस्तुत किए। पहला काम, दोनों देशों की आर्थिक संपूरकताओं का लाभ उठाने के लिए आर्थिक साझेदारी रूपरेखा तैयार करना था। उन्होंने मुक्त व्यापार के विचार को बढ़ावा देने के लिए मिलकर काम करने का सुझाव दिया था। तीसरा प्रस्ताव प्रशांत और हिन्द महासागर क्षेत्रों को एकीकृत करके एकल आर्थिक क्षेत्र बनाने हेतु संयुक्त प्रयास करना था।[11]

सियोल तक नई दिल्ली की पहुंच शीत युद्ध की समाप्ति और घरेलू आर्थिक सुधार हेतु आवश्यक भारतीय विदेश नीति में रणनीतिक बदलाव का एक अभिन्न अंग था। कोरिया के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करना इस कदम के केंद्र में था, जैसे कि लुक ईस्ट पॉलिसी के पहले दशक के दौरान कई अन्य पूर्वी एशियाई देशों के मामले में हुआ है। इस तथ्य को ध्यान में रखना दिलचस्प है कि जापान के साथ भारत के लंबे मैत्रीपूर्ण संबंधों के बावजूद, टोक्यो भारत के आर्थिक सुधारों के बारे में आश्वस्त नहीं था इसलिए एलईपी पर उसकी प्रतिक्रिया बहुत धीमी रफ्तार से मिली। दूसरी ओर, कोरिया ने भारतीय अर्थव्यवस्था के दरवाजे खुलने से मिले अवसरों को भुनाने के प्रयास में त्वरित प्रतिक्रिया दी। आर्थिक और तकनीकी शक्ति के रूप में कोरिया के उदय ने भारत को अपने आर्थिक परिवर्तन को सुविधाजनक बनाने में एक साझीदार तलाश करने का अवसर दिया। वर्ष 1993 में दक्षिण कोरिया और भारत के बीच द्विपक्षीय व्यापार करीब 600 मिलियन डॉलर था जो 2008 में बढ़ कर करीब 15.6 बिलियन डॉलर का हो गया।[12] 1990 के दशक के मध्य से निवेश के पैमाने और गुणवत्ता ने व्यापार में महत्वपूर्ण वृद्धि कराई। कोरियाई समूह ने पीएम राव के आह्वान पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी और भारतीय अर्थव्यवस्था के खुलने से मिले अवसर को जल्दी से भुना लिया। आरंभ से, दक्षिण कोरिया, 1.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर के कुल विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) के साथ, 1996 और 2001 के बीच, भारत में सबसे प्रमुख एशियाई निवेशक बन गया।[13] इस अवधि में एलजी, सैमसंग, हुंडई और देवू जैसे कोरियाई समूहों द्वारा निवेश किया गया और बाद में उन्होंने खुद को भारतीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण खिलाड़ियों के रूप में स्थापित किया।[14]

शीत युद्ध के बाद की अवधि में नई दिल्ली का सियोल के प्रति नजरिया भी स्पष्ट था जिसने शीत युद्ध युग के आदर्शवाद को पीछे छोड़ते हुए विदेश नीति के लिए एक व्यावहारिक और भौतिकवादी दृष्टिकोण को व्यक्त किया। इस संबंध में, दक्षिण कोरिया के साथ अपने संबंधों पर ध्यान देते हुए नई दिल्ली ने सियोल और प्योंगयांग के साथ अपने संबंधों में समान दूरी बनाए रखी।[15] 1990 के दशक के दौरान, भारत और कोरिया पुनर्खोज की प्रक्रिया से गुजरे। हालांकि, वे 1990 के दशक के आरंभ की गति को बनाए नहीं रख सके। वर्ष 1996 में राष्ट्रपति किम यंग- सैम की भारत यात्रा के बाद प्रमुख नेताओं का अगला दौरा आठ वर्षों के अंतराल पर हो सका। इसी प्रकार, संयुक्त आयोग, विदेश मंत्रियों की सह-अध्यक्षता वाला एक द्विपक्षीय संवाद तंत्र, हालांकि राष्ट्रपति किम की भारत यात्रा के दौरान बनाया गया था, 2002 में काम करना शुरू कर सका। दोनों देशों के बीच संबंधों में निष्क्रियता के लिए, 1997 के एशियाई वित्तीय संकट और 1998 में भारत द्वारा किए गए परमाणु परीक्षण को मुख्य रूप से जिम्मेदार ठहराया जा सकता है।

3. रणनीतिक साझेदार बनानाः समेकन काल

2000 के दशक के मध्य से, भारत-कोरिया संबंधों में नई प्रगति देखने को मिलती है। नई दिल्ली और सियोल के बीच संबंधों के इस चरण की चार महत्वपूर्ण विशेषताएं थीं। पहला, उच्च स्तर के अधिकारों/नेताओं की बार-बार यात्राओं के माध्यम से राजनीतिक संबंधों को मजबूत और द्विपक्षीय संवाद संत्र को संस्थागत बनाना। दूसरा, रक्षा, सुरक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, बुनियादी ढांचे आदि को

शामिल करने के लिए वाणिज्यिक एवं आर्थिक संबंधों से परे द्विपक्षीय एजेंडे के विस्तार के साथ संबंधों ने एक व्यापक स्वरूप प्राप्त किया। तीसरा, इस अवधि में आर्थिक संबंधों की गहनता और पहले से अधिक समेकन देखा गया। वर्ष 2009 में सीईपीए पर हस्ताक्षर करना द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों के विकास में एक महत्वपूर्ण घटना रही। अंत में, इस चरण के दौरान, दोनों देशों ने, 2010 में, आधिकारिक तौर पर रणनीतिक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर करने के साथ संबंधों के रणनीतिक मूल्य को मान्यता दे दी।

इस चरण के दौरान भारतीय दृष्टिकोण से भारत-कोरिया संबंधों में विकास, एलईपी के दूसरे चरण के माध्यम से स्पष्ट रूप से पूर्व एशियाई जुड़ाव का हिस्सा था। यद्यपि शीत शुद्ध की समाप्ति ने पूर्वी एशिया के देशों के साथ भारत के संबंधों के लिए एक माहौल तैयार किया लेकिन परमाणु मुद्दों ने प्रक्रिया को जटिल बना दिया। हालांकि, अंतरराष्ट्रीय समुदाय में नई दिल्ली का पोखरण के बाद का अलगाव न केवल एक अल्पकालिक घटना थी बल्कि इस घटना ने क्षेत्र में इसकी स्थिति को और बेहतर बनाने का भी मार्ग प्रशस्त किया। नई दिल्ली द्वारा वाशिंगटन के साथ परमाणु मुद्दों के सफल समाधान और भारत- अमेरिका परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर ने वास्तव में इससे संबंधों को, विशेष रूप से इस क्षेत्र में अमेरिकी सहयोगियों- जापान और कोरिया के साथ सहज बनाया।[16] पुनः सक्रिए एलईपी ने आर्थिक संबंधों से परे एजेंडे को व्यापक बनाया और पूर्वोत्तर एशिया और ओशिनिया को शामिल करने के लिए भौगोलिक दायरे का विस्तार किया। वर्ष 2003 में भारत के एलईपी के दूसरे चरण की घोषणा करते हुए विदेश मंत्री यशवंत सिन्हा ने कहाः

"भारत की लुक ईस्ट पॉलिसी का पहला चरण आसियान-केंद्रित था और मुख्य रूप से व्यापार एवं निवेश संबंधों पर केंद्रित था। इस नीति के नए चरण में 'ईस्ट' की परिभाषा में विस्तार किया गया है जो ऑस्ट्रेलिया से पूर्वी एशिया तक फैली हुई है, जिसका उद्देश्य आसियान है। नया चरण व्यापार से व्यापक आर्थिक एवं सुरक्षा संबंधी मुद्दों पर बदलाव के बारे में भी है जिसमें समुद्री रेखा की रक्षा हेतु संयुक्त प्रयास और आतंकवाद विरोधी गतिविधियों पर समन्वय शामिल है। आर्थिक पक्ष में, दूसरे चरण में एफटीए के लिए व्यवस्था और क्षेत्र के देशों एवं भारत के बीच संस्थागत आर्थिक संबंध स्थापित करना अभिलक्षित है।[17]

भारत के एलईपी का दूसरा चरण उस बढ़ते परवाह का भी, विशेष रूप से इसके एक दशक से चल रहे उच्च आर्थिक विकास के संदर्भ में, प्रतिबिंब था जो कोरिया समेत क्षेत्रीय देशों द्वारा भारत के लिए दिखाई दिया।[18] वर्ष 2001 में प्रकाशित ब्रिक रिपोर्ट की लोकप्रियता, जिसमें भारत को इक्कीसवीं सदी के मध्य तक विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की भविष्यवाणी की थी, ने 'राइजिंग इंडिया' की छवि को और मजबूत किया।[19] एलईपी के पहले चरण के निर्माण में, दूसरे चरण में बहुपक्षीय और द्विपक्षीय, दोनों स्तरों पर पूर्वी एशिया के साथ भारत के संबंधों का विस्तार हुआ। बहुपक्षीय मोर्चे पर, फिर से सक्रिए एलईपी ने 2005 में पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन (ईएएस) और 2006 में एशिया-यूरोप बैठक (एएसईएम) में भारत की सदस्यता के दरवाजे खोल दिए।[20] भारत की बेहतर होती स्थिति को स्वीकार करते हुए, कोरिया ने विकासशील पूर्वी एशियाई क्षेत्रीय समुदाय में भारत के बढ़ते एकीकरण का स्वागत किया। पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन में भारत की सदस्यता का स्वागत करने पर, तत्कालीन विदेश मंत्री बान की-मून ने 2005 में कहा था,

"एक महान देश का दर्जा... (भारत की) पहुंच के भीतर लगता है क्योंकि यह आने वाले दशकों में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरने के रास्ते पर है। वैश्वीकरण के पथ पर बढ़ने और क्षेत्रवाद के उद्भव ने कोरिया-भारत सहयोग के लिए नए रास्ते खोल दिए हैं। 21वीं सदी के

आरंभ में वैश्वीकरण और क्षेत्रवाद के प्रसार के साथ तालमेल रखने के लिए, कोरिया और भारत वैश्विक एवं क्षेत्रीय दोनों स्तरों पर एक दूसरे के साथ सक्रिय रूप से सहयोग कर रहे हैं। भारत की 'लुक ईस्ट' पॉलिसी ने कोरिया समेत एशियाई देशों के साथ इसकी साझेदारी को मजबूत बनाने में बहुत योगदान दिया है। मुझे यह कहते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही है कि कोरिया 'प्रथम पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन' के सदस्य के रूप में भारत का तहे दिल से स्वागत करता है।"[21]

21वीं सदी में मध्य स्तर के शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में कोरिया का उदय पूर्वी एशिया में नई दिल्ली की पहुंच को पूरा बना रहा है और इसकी सक्रिए कूटनीति भी भारत-कोरिया संबंधों को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण कारक रही है।[22] 1997 के एशियाई वित्तीय संकट से कोरिया की तेजी से रिकवरी ने 21वीं सदी में एक महत्वपूर्ण आर्थिक और तकनीकी शक्ति के रूप में अपनी छवि को मजबूत किया। 2010 में जी20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करने वाले पहले एशियाई देश के रूप में, 2012 में परमाणु शिखर सम्मेलन और कई अन्य हाई-प्रोफाइल अंतरराष्ट्रीय राजनयिक पहलों की मेजबानी ने मध्य स्तर के शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में कोरिया की स्थिति को मजबूत करने में मदद की।[23]

दो संरचनात्मक आख्यानों की विश्वसनीयता, जिसने अंतरराष्ट्रीय मामलों में एजेंसी को नई दिल्ली और सियोल को उत्तरदायी ठहराया, ने भी द्विपक्षीय संबंधों को नया रूप देने में मदद की। 21वीं सदी की शुरुआत के बाद से दो आख्यान 'एशियन सेंचुरी' हैं और 2008 के वित्तीय संकट के संदर्भ में 'राइज ऑफ द रेस्ट' उभरा। एशियन सेंचुरी कथा में एशिया को वैश्विक राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक क्षेत्र का केंद्र बनने की परिकल्पना की गई है, जिसने दो तरह से द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर बनाने में मदद की है। सबसे पहले, विश्व मामलों के गुरुत्वाकर्षण के भविष्य के केंद्र के रूप में एशिया की कल्पना ने भारत और कोरिया की विदेश नीतियों में एक स्थानिक सम्मिलन लाया क्योंकि उन्होंने 'एशिया केंद्रित' विदेश नीति प्रथाओं को अपनाना शुरू किया। यह भारत के एलईपी और कोरिया के न्यू एशिया इनिशिएटिव के सम्मिलन में परिलक्षित हुआ है।[24] आसियान केंद्रित क्षेत्रीय मंचों समेत कई एशिया केंद्रित क्षेत्रीय संस्थानों में उनकी साझेदारी के माध्यम से इस स्थानिक सम्मिलन को और मजबूत किया गया। दूसरे, एशिया की तीसरी और चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, भारत और कोरिया के बीच संबंधों को एशियाई सदी के वादे को साकार करने में एक आवश्यक परिणाम्य के रूप में देखा गया है। एशियाई शताब्दी के संदर्भ में भारत-कोरिया संबंधों पर प्रकाश डालते हुए दिवंगत राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने, जब वे विदेश मंत्री थे, कहा थाः

"कोरिया के साथ भारत के संबंधों को मजबूत करना हमारी सरकार की विदेश नीति में उच्च प्राथमिकता का विषय है...भारत और कोरिया एक नई एशियाई गतिशीलता की इस पृष्ठभूमि के खिलाफ घनिष्ठ सहयोग चाहते हैं और यह स्पष्ट है कि हमारी बातचीत केवल द्विपक्षीय रूप से महत्वपूर्ण नहीं है। हम अपने सहयोग को इस प्रकार से तैयार करने की जिम्मेदारी साझा करते हैं जो पूरे क्षेत्र की रचनात्मक ऊर्जा को मुक्त करने में मदद करता है और राजनीतिक एवं आर्थिक वास्तुकला का प्रयोग करता है जो स्थिरता और समृद्धि के पूर्व-प्रतिष्ठित क्षेत्र के रूप में एशिया के उद्भव के लिए अनुकूल है और जो सही मायनों में इसे 21वीं सदी का एशियाई सदी बना सकता है"।[25]

'राईज ऑफ द ईस्ट' का इतिहास, संक्षेप में, अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में सत्ता के पुनर्वितरण पर प्रकाश डालते हुए, अंतरराष्ट्रीय मामलों की एक पुनर्गठित स्थिति की छवि प्रस्तुत करती है।[26] 2008 के वित्तीय संकट के बाद की अवधि में वैश्विक शासन के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए जी7 को सबसे प्रमुख मंच के रूप में विस्थापित करते हुए, जी20 के अस्तित्व ने बहुत ध्यान आकर्षित किया। इसके अलावा, पुनर्गठित वैश्विक शक्तिशाली राष्ट्र संरचना जहां भारत और कोरिया उच्च राजनयिक तालिका

के सदस्य बन गए हैं, ने, उनकी पारस्परिक धारणा और उनके द्विपीय संबंधों के महत्व को एक नए नज़रिए से पुनर्गठित करने में मदद की।[27]

वर्ष 2004 में कोरियाई राष्ट्रपति रोह मू- ह्युन की भारत यात्रा के दौरान द्विपक्षीय संबंधों में नई गतिशीलता दिखाई दी। आठ साल की अवधि के बाद हुई शिखर बैठक में, द्विपक्षीय संबंधों को "शांति और समृद्धि के दीर्घकालिक सहकारी साझेदारी" में बदल दिया गया। तत्कालीन भारतीय राष्ट्रपति डॉ. अब्दुल कलाम के अनुसार, संबंधों की स्थिति में सुधार,

"हमारे संबंधों को उसके द्विपक्षीय आयामों से परे और दीर्घकालिक और रणनीतिक परिप्रेक्ष्य में देखने की हमारी प्रतिबद्धता का संकेत दिया। आज हम मानते हैं कि भारत- कोरिया संबंधों का हमारे क्षेत्र और एशियाई महाद्वीप की शांति, स्थिरता और विकास पर महत्वपूर्ण प्रभाव है। एशिया में क्षेत्रीय एकीकरण की अपरिवर्तनीय प्रवृत्ति के साथ, हम कोरिया को अपनी "लुक ईस्ट" पॉलिसी में एक प्रमुख तत्व के रूप में और शांति एवं समृद्धि के एक गतिशील और जीवंत संपूर्ण एशियाई समुदाय के लिए हमारी दृष्टि में एक विश्वसनीय भागीदार के रूप में देखते हैं"।[28]

राष्ट्रपति रोह की यात्रा के दौरान दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने की दिशा में कई नई पहलों का प्रस्ताव दिया। संयुक्त सचिव स्तर पर एक नया संवाद तंत्र- विदेश नीति और सुरक्षा संवाद स्थापित करने का निर्णय लिया गया। रक्षा और सुरक्षा, ऊर्जा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष, कनेक्टिविटी और लोगों से लोगों के आदान-प्रदान के क्षेत्र में द्विपक्षीय संबंधों के दायरे का विस्तार करने पर भी सहमति हुई। विज्ञान और प्रौद्योगिकी में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए उप-मंत्री/सचिव स्तर पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विषय पर कोरिया- भारत संयुक्त समिति का शुभारंभ किया गया। पहली संयुक्त समिति की बैठक 2005 में आयोजित की गई थी। आर्थिक संबंधों को गहरा करने के लिए नेतृत्व ने एक संयुक्त अध्ययन समूह स्थापित करने का निर्णय लिया।[29]

वर्ष 2009 में हस्ताक्षरित सीईपीए संयुक्त अध्ययन की अनुशंसा पर आधारित था। कोरिया ओईसीडी का पहला देश था जिसके साथ भारत ने मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए। रक्षा के क्षेत्र में, दोनों पक्षों ने 2005 में रक्षा उद्योग और रसद पर समझौता ज्ञापन के रूप में पहला समझौता किया था। भारतीय और कोरियाई तटरक्षक बल ने 2006 में दोनों देशों के बीच समुद्री सहयोग को मजबूत बनाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया था।

जैसा कि पहले बताया गया है, उच्च-स्तरीय दौरों की संख्या में होने वाली वृद्धि ने दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों में गति बनाए रखने में मदद की। इस संबंध में, 2006 में, डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम का दौरा, जो भारत के किसी भी राष्ट्रपति का पहला कोरिया दौरा था, उल्लेखनीय है। दौरे के दौरान राष्ट्रपति कलाम ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग की क्षमता और महत्व पर जोर दिया था।

वर्ष 2010 में गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में कोरिया के राष्ट्रपति ली म्युंग- बाक का भारत दौरा, भारत- कोरिया संबंधों का एक ऐतिहासिक क्षण था। दौरे के दौरान, दोनों देशों ने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया था। कोरिया के साथ रणनीतिक साझेदारी बनाने के तर्क पर भारत के विदेश मंत्री प्रणब मुखर्जी ने 2007 में अपने कोरिया दौरे के दौरान कहा था कि,

"आपके महान देश (कोरिया) के साथ हमारी 'शांति और समृद्धि हेतु हमारी दीर्घकालिक सहकारी साझेदारी', भारत की लुक ईस्ट पॉलिसी की आधारशिला है। जिस तेजी से एलजी, हुंडई और सैमसंग भारत के घर- घर में लोकप्रिय हुए हैं उससे मेरे साथी भारतीय और मैं स्वयं भी चकित हूँ। अब हम सीईपीए पर बातचीत कर रहे हैं और हमारा व्यापार समय- समय पर निर्धारित लक्ष्यों से बेहतर प्रदर्शन

कर रहा है। हाल ही में, अन्य क्षेत्रों में भी हमारे संबंधों का विस्तार हुआ है और मेरा दृढ़ विश्वास है कि हमें अपनी द्विपक्षीय साझेदारी को अगले स्तर तक ले जाने के लिए रणनीतिक नीति बनाने की आवश्यकता है।"[30]

रणनीतिक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर करने के अवसर पर जारी संयुक्त बयान में दोनों देशों के बीच साझेदारी को मजबूत करने के लिए विस्तृत रोडमैप दिया गया था।[31] नई दिल्ली और सियोल ने कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए और विदेश नीति एवं सुरक्षा वार्ता को उप-विदेश मंत्री/ सचिव (पूर्व) स्तर तक अपग्रेड करने की भी घोषणा की। हस्ताक्षरित समझौतों में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ईसरो) और कोरिया एयरोस्पेस रिसर्च इंस्टीट्यूट (केएआरआई) के बीच अंतरिक्ष सहयोग पर समझौता ज्ञापन और सूचना प्रौद्योगिकी एवं सेवाओं में सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन शामिल है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए, दोनों देशों ने संयुक्त अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए 10 मिलियन डॉलर (जिसमें दोनों पक्ष 5- 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान करता) का समर्पित कोष बनाने निर्णय लिया था। वर्ष 2009 में हस्ताक्षरित और 2010 में लागू किए गए सीईपीए समझौते के तहत दोनों नेताओं ने 2014 के लिए 30 अरब डॉलर का महत्वाकांक्षी लक्ष्य भी निर्धारित किया था। शिखर सम्मेलन में नागरिक परमाणु ऊर्जा सहयोग के क्षेत्र में जबरदस्त झुकाव दिखा और इस क्षेत्र में सहयोग को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया भी शुरू की गई। इस संबंध में, दोनों देशों ने 2011 में भारत की राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल के कोरिया दौरे के दौरान भारत-कोरिया नागरिक परणामु समझौते पर हस्ताक्षर किए।

नई दिल्ली और सियोल के बीच बढ़ते रक्षा और सुरक्षा सहयोग ने भारत-कोरिया द्विपक्षीय संबंधों के रणनीतिक महत्व पर बल दिया। वर्ष 2010 में भारतीय रक्षा मंत्री के पहले कोरिया दौरे के साथ रक्षा संबंधों ने नई गति पाई। रक्षा मंत्री एके एंटनी के दौरे के दौरान, नई दिल्ली और सियोल ने रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए दो समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। एक समझौता ज्ञापन दोनों सेनाओं के बीच सेवा कर्मियों के आदान-प्रदान की सुविधा प्रदान करने और दूसरा रक्षा औद्योगिक सहयोग पर था। भारत ने सियोल स्थित अपने दूतावास में एक स्थायी सैन्य सहचर भी बनाया। इस अवधि में दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच संयुक्त नौसैनिक अभ्यास और पोर्ट कॉल में भी वृद्धि देखी गई। वर्ष 2014 में राष्ट्रपति पार्क गुएन-हे के भारत दौरे के दौरान, दोनों देशों ने गोपनीय सैन्य सूचना संरक्षण अनुबंध पर हस्ताक्षर किए और साइबर सुरक्षा पर समझौता ज्ञापन को अंतिम रूप दिया गया जिससे दोनों देशों के बीच सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ा। दोनों पक्ष दोनों देशों के दो राष्ट्रीय सुरक्षा प्रतिष्ठानों के बीच नियमित परामर्श बनाए रखने पर भी सहमत हुए।[32]

प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के एक- के- बाद- एक कोरिया के दो दौरे, 2010 में जी-20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए और 2012 में राजकीय यात्रा, के बाद, 2014 में कोरिया के राष्ट्रपति का भारत दौरा और अंतरराष्ट्रीय राजनयिक घटनाओं के दौरान कई शिखर बैठकों ने दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी की गति को बनाए रखने में मदद की। इस अवधि में भारत-कोरिया वित्त मंत्रियों की बैठक, भारत- कोरिया विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रियों की संचालन समिति की बैठक, भारत-कोरिया रक्षा मंत्रियों की बैठक आदि समेत मंत्रिस्तरीय दौरों और मंत्री स्तर पर कई परामर्श संस्थाओं की स्थापना भी हुई।

इस चरण के दौरान द्विपक्षीय संबंधों की एक अन्य विशेषता पारा- डिप्लोमेसी का उदय है जहां राज्य सरकारों समेत उप-राष्ट्रीय नेता द्विपक्षीय संबंधों की भूमिका निभाते हैं।[33] वचनबद्धता का मुख्य चैनल प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों का कोरिया दौरा रहा है। भारत के राज्य भी व्यापाक गतिविधियों

में शामिल रहे हैं जिसमें रोड शो और अन्य व्यावसायिक बैठकें भी शामिल हैं। भारत के राज्य सरकारों द्वारा कोरिया तक पहुंच, 2000 के दशक के मध्य से, द्विपक्षीय संबंधों की एक महत्वपूर्ण विशेषता रही है और हाल के वर्षों में इसमें तेजी आई है। भारत की पारा-डिप्लोमेसी प्रयासों को कोरिया के उप-राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा ऐसी ही गतिविधियों, जिसमें प्रान्त और शहर शामिल हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत में कोरिया के दूतावास द्वारा भारत के राज्यों में अपनी आउटरीच गतिविधियों के माध्यम से, पूरित किया गया है। नई दिल्ली स्थित कोरिया दूतावास 'कोरियन कारवां' नाम से सांस्कृतिक और व्यावसायिक प्रचार कार्यक्रम का आयोजन करता रहा है।[34]

4. विशेष रणनीतिक साझेदारी के माध्यम से संबंधों में मजबूत बनाना

वर्ष 2015 में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की कोरिया यात्रा ने भारत-कोरिया द्विपक्षीय संबंधों को एक नई गति प्रदान की। दौरे के दौरान, द्विपक्षीय संबंधों की स्थिति को 'विशेष रणनीतिक साझेदारी' में अपग्रेड किया गया था। प्रधानमंत्री मोदी के अनुसार, यह उन्नयन, "यह बताता है कि हम अपने संबंधों की नई रूपरेखा को कितनी गंभीरता से लेते हैं"।[35] रणनीतिक संचार- व्यवस्था को मजबूत करने के लिए, नेता उप-मंत्री/ सचिव स्तर पर "2+2 विदेश और रक्षा वार्ता" करने पर सहमत हुए। भारत की विदेश नीति में कोरिया को दी गई प्राथमिकता पर रौशनी डालते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहाः "कोरिया गणराज्य ऐसा दूसरा राष्ट्र है जिसके साथ भारत 2+2 प्रारूप में राजनयिक और सुरक्षा वार्ता करेगा।"[36]

कोरिया तक भारत की पहुंच में प्रधानमंत्री मोदी की संचालन भूमिका महत्वपूर्ण कारक रही है। भारत के प्रधानमंत्री बनने से भी पहले, मोदी भारत-कोरिया संबंधों को मजबूत बनाने के लिए सक्रिए थे। गुजरात के मुख्यमंत्री (2001-14) के रूप में काम करते हुए, मोदी ने कोरिया के आर्थिक परिवर्तन की प्रशंसा की थी और इसे भारत द्वारा अनुसरण किए जाने वाले मॉडल के रूप में देखा था। मोदी ने कहा था कि वे, "गुजरात को दक्षिण कोरिया के जैसा बनाना चाहते हैं"।[37] प्रधानमंत्री बनने के बाद, उन्होंने कहा कि "भारत बहुत कुछ हासिल करना चाहता है जो कोरिया पहले ही कर चुका है" और यह कि "जो क्षेत्र कोरिया में मजबूत हैं वे मेरे देश के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं।"[38] भारत-कोरिया संबंधों के एक आवश्यक स्तंभ के रूप में 'विकास साझेदारी' की परिकल्पना करते हुए, पीएम मोदी ने अपनी सियोल यात्रा के दौरान "कोरिया, बारत के आर्थिक आधुनिकीकरण में एक महत्वपूर्ण भागीदार" घोषित किया।[39] साझेदारी के लिए पहचान किए गए प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में रक्षा उत्पादन, विशेष रूप से स्मार्ट सिटी परियोजनाओं में बुनियादी ढांचा विकास, जहाज निर्माण, परिवहन और रसद समेत समुद्री सहयोग और स्टील एवं इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर निर्माण पर ध्यान केंद्रित करने वाला औद्योगिक सहयोग शामिल है।[40]

कोरिया तक भारत की पहुंच ने विदेश नीति के प्रति मोदी सरकार के नए दृष्टिकोण को भी प्रतिबिंबित किया जिसका उद्देश्य भारत की क्षेत्रीय और वैश्विक रूपरेखा में सुधार लाना था।[41] विदेश नीति में विकास पहलुओं पर अधिक जोर देने से कोरिया जैसी उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के साथ विकास साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए नई दिल्ली की दिलचस्पी को और बढ़ावा मिला।[42] इस दिशा में, भारत ने नई सरकार की 'मेक इन इंडिया', 'डिजिटल इंडिया', और 'स्मार्ट सिटी परियोजना' जैसी प्रमुख पहलों में कोरिया की भागीदारी को प्रोत्साहित किया। भारत ने अपने पूर्वी एशिया संबंधों में सुधार और दो दशक पुरानी 'लुक ईस्ट पॉलिसी' को 'एक्ट ईस्ट पॉलिसी' में अपग्रेड कर दोनों देशों को और करीब लाया।[43] हालांकि एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत भारत- कोरिया संबंधों को आकार देने में आर्थिक और विकास के एजेंडे को प्राथमिकता दी गई, रणनीतिक अनिवार्यता भी स्पष्ट रही है। चीन के उदय के साथ बदलती

क्षेत्रीय भू-राजनीतिक व्यवस्था के संदर्भ में, एक्ट ईस्ट पॉलिसी एक बहुआयामी दृष्टिकोण के माध्यम से भारत की तार्किक प्रतिक्रिया रही है जो इस क्षेत्र में बीजिंग की मुखरता को रोकता दिखता है। एईपी के तहत, भारत ने आसियान के देशों, जापान, कोरिया और ऑस्ट्रेलिया के साथ रक्षा और सुरक्षा संबंधों को मजबूत बनाकर अपनी क्षेत्रीय स्थिति में सुधार किया है और हिन्द-प्रशांत की अवधारणा के माध्यम से क्षेत्रीय सुरक्षा संरचना हेतु अपने विज़न को बढ़ावा दे रहा है।[44]

प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व और नई दिल्ली में बहुमत की सरकार के गठन ने कोरिया का अभिप्रायपूर्ण ध्यान आकर्षित किया है। कोरियाई शिक्षाविद् के अनुसार, भारत में नए राजनीतिक परिदृश्य ने कोरिया में तीसरी 'भारत लहर' पैदा की और इसे कोरियाई व्यापार के लिए एक अवसर के रूप में देखा।[45] नई सरकार के शक्तिशाली विकासात्मक आख्यान और आर्थिक सुधारों के वादे को भारत में पोस्को निवेश की विफलता के बाद भारत के बारे में कोरियाई व्यापार के निराशावादी रवैये को दूर करने में मददगार के रूप में देखा गया था।[46]

वर्ष 2017 में राष्ट्रपति मून जे-इन के सत्ता में आने के बाद सियोल ने नई दिल्ली के दृष्टिकोण को नई भारत नीति के साथ पूरक बनाया। 'पूर्वोत्तर एशिया प्लस/ नॉर्थईस्ट एशिया प्लस'[47] के विज़न के तहत राष्ट्रपति मून ने कोरियाई विदेश नीति में नई दिल्ली के दर्जे को अपने परंपरागत भागीदारों जैसे अमेरिकी, चीन, जापान और रूस के समकक्ष किया। अपने तरह के पहले प्रयास में राष्ट्रपति मून ने राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने के तुरंत बाद विशेष राष्ट्रपति दूत को भारत भेजा। 'नई दक्षिण नीति/ न्यू सदर्न पॉलिसी (एनएसपी)'- एक रणनीति जिसमें राष्ट्रपति के आर्थिक सलाहकार की अध्यक्षता में ग्यारह मंत्रालय शामिल है, की घोषणा के बाद, भारत और आसियान देशों के साथ कोरिया के संबंधों को मजबूत करने के सांकेतिक संकेत मिलते हैं।[48]

दो कारक हैं जो भारत में कोरिया की पहुंच को रेखांकित करते हैं- आर्थिक विविधता जिसका उद्देश्य चीन पर सियोल की निर्भरता को कम करना है और पूर्वोत्तर एशिया से परे राजनयिक क्षेत्र का विस्तार करना। सियोल की भारत और आसियान की धुरी में चीन का कारक बड़ा था (कुमार 2018)। कोरिया की चीन संबंधी दुविधा चीन के साथ उसके गहरे आर्थिक जुड़ाव की बढ़ती नकारात्मक धारणा से जुड़ी है। अतीत में, सियोल ने चीन के उदय को आर्थिक अवसर के रूप में देखा था।[49] इसके बाद, चीन कोरिया का सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक भागीदार बन गया। इन वर्षों में, चीन कोरिया के सबसे महत्वपूर्ण निवेश गंतव्य के रूप में उभरा है और इसके कुल व्यापार का लगभग एक-चौथाई है। वर्ष 2016 में दोनों देशों के बीच टीएचएएडी (THAAD) विवाद और इसके आर्थिक गिरावट ने कोरिया को चीन के प्रति अपने नजरिए का पुनर्मूल्यांकन करने को विवश किया।[50] एनएसपी के माध्यम से, सियोल इस दृष्टि से विविधीकरण की रणनीति अपनाता हुआ प्रतीत होता है कि चीन पर आर्थिक निर्भरता ने कोरिया को राजनीतिक जोखिमों के प्रति संवेदनशील बना दिया है।

एनएसपी का दूसरा उद्देश्य पूर्वोत्तर एशिया से परे सियोल के राजनयिक क्षितिज का विस्तार करना है। कोरियाई विदेश नीति परंपरागत रूप से कोरियाई प्रायद्वीप मामलों और चार क्षेत्रीय शक्तियों के साथ द्विपक्षीय संबंधों के प्रबंधन पर केंद्रित रही है- अमेरिका, चीन, रूस और जापान।[51] एक संकीर्ण-केंद्रित विदेश नीति जो अतीत में कोरिया के लिए लाभकारी रही ती, हालांकि, दो कारणों से लगातार असंगत होती जा रही है। सबसे पहले, मध्य शक्ति के रूप में उभरने के साथ कोरिया के रणनीतिक हित कोरियाई प्रायद्वीप से आगे बढ़ गए हैं।[52] इस बीच, बढ़ते चीन के संदर्भ में नई क्षेत्रीय रणनीतिक वास्तविकताओं को समायोजित करने के लिए सियोल पर अपनी विदेश नीति में समायोजन करने का भी दबाव रहा है। पिछले तीन दशकों के दौरान, कोरिया वाशिंगटन के साथ अपने सुरक्षा गठबंधन को

बनाए रखते हुए सफलतापूर्वक बीजिंग के साथ अपने आर्थिक संबंधों को मजबूत करने में सफल रहा है। हालांकि, अमेरिका और चीन के बीच बढ़ती रणनीतिक प्रतिस्पर्धा कोरिया को युद्धाभ्यास और स्वायत्तता के लिए विवश कर रही है। सियोल पर अपनी विदेश नीति की स्थिति को पुनर्गठित करने के लिए दबाव डालने वाला एक अन्य कारक वाशिंगटन से उभरती अनिश्चितता है। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के शासन में अमेरिकी विदेश नीति में अलगाववादी और संरक्षणवादी प्रवृत्तियों ने वाशिंगटन की सुरक्षा प्रतिबद्धताओं और उदार अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को बनाए रखने के लिए उसके नेतृत्व के बारे में कोरिया सहित उसके सहयोगियों के बीच संदेह पैदा किया।[53] हालांकि 'अमेरिका फर्स्ट' वाक्पटुता अब राष्ट्रपति जो बाइडेन के शासन में अमेरिकी विदेश नीति का हिस्सा नहीं है, लेकिन अलगाववादी और संरक्षणवादी प्रवृत्ति अभी भी बनी हुई है। अनिश्चितता और परिवर्तन के संदर्भ में, सियोल की भारत और आसियान देशों तक पहुंच को बदलते क्षेत्रीय परिवेश में अपने राजनयिक लाभ को बढ़ाने के लिए एक रणनीतिक कदम के रूप में देखा जाना चाहिए।[54]

राष्ट्रपति मून की भारत यात्रा के दौरान जारी किया गया संयुक्त विज़न दस्तावेज एक्ट ईस्ट पॉलिसी (एईपी) और एनएसपी के बीच हितों के सम्मिलन को दर्शाता है। दस्तावेज तीन क्षेत्रों में भारत-कोरिया संबंधों के भविष्य का मार्ग दर्शाता है- जनता, समृद्धि और शांति।[55] द्विपक्षीय संबंधों के लिए जन-केंद्रित दृष्टिकोण अपनाकर, संयुक्त विज़न ने द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने में गैर-राज्य अभिकर्ताओं की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया। विज़न में लोगों के बीच आदान-प्रदान, कनेक्टिविटी और अधिक दृष्यता और सामान्य लोगों के बीच एक दूसरे को समझने पर जोर दिया गया। समृद्धि पर, संयुक्त दृष्टि ने भारत की तेज़ आर्थिक वृद्धि और इसके अत्यधिक कुशल कार्यबल और कोरिया की तकनीकी कौशल, विनिर्माण उत्कृष्टता और विकासात्मक अनुभव के बीच पूरकताओं का लाभ उठाने पर जोर दिया। फरवरी 2019 में पीएम मोदी का कोरिया के दौरे ने एईपी और कोरिया के एनएसपी की बैठक के जरिए द्विपक्षीय संबंधों के ऐतिहासिक रूपरेखा को बनाए रखने में मदद की। पीएम मोदी की यात्रा के दौरान, भारत और कोरिया ने स्टार्ट-अप, बुनियादी ढांचे के विकास, मीडिया, सीमा पार और अंतर्राष्ट्रीय अपराध सहित सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए सात समझौतों पर हस्ताक्षर किए।[56]

ऐसे में जबकि विशेष रणनीतिक साझेदारी (एसएसपी) के लिए द्विपक्षीय संबंधों का उत्थान नई घरेलू और अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक वास्तविकताओं द्वारा आवश्यक एक प्रतीकात्मक संकेत था लेकिन किसी भी तरह से पलायन नहीं था बल्कि इसे पिछले दशक में हुई प्रगति को बनाए रकने के लिए एक नए प्रयास के रूप में देखा जाना चाहिए। छह विशेषताएं एसएसपी के तहत भारत-कोरिया संबंधों के विकास पर रौशनी डालती हैं। पहला, कोविड-19 महामारी के दौरान बाधित होने से पहले तक उच्च-स्तरीय दौरों के माध्यम से दोनों देशों के बीच राजनीतिक संबंधों को मजबूत करना है। महामारी के दौरान भी, वर्चुअल मीटिंग्स के माध्यम से एक निश्चित स्तर की बातचीत को बनाए रखा गया था। इस चरण के दौरान, भारत और कोरिया ने शिखर सम्मेलन स्तर की आठ बैठकें कीं जिसमें बहुपक्षीय राजनयिक कार्यक्रमों के दौरान बैठक, भारत की ओर से बारह मंत्रिस्तरीय प्रतिनिधिमंडलों का कोरिया जाना और कोरिया से ग्यारह मंत्रिस्तरीय प्रतिनिधिमंडलों का भारत आना शामिल था।[57] प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मून के बीच मजबूत व्यक्तिगत तालमेल एक महत्वपूर्ण अनवस्थित है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक-दूसरे को भेजे उनके संदेश ने भारत-कोरिया संबंधों की दृश्यता बढ़ाने में मदद की। अन्य आदान-प्रादान में विभिन्न भारतीय राज्यों के मुख्यमंत्री स्तर के छह प्रतिनिधिमंडल का कोरिया जाना और लोक सभा अध्यक्ष के नेतृत्व में संसदीय प्रतिनिधिमंडल का विनिमय शामिल

है। दूसरी विशेषता विशेष रक्षा- औद्योगिक क्षेत्र में रक्षा और सुरक्षा सहयोग में महत्वपूर्ण विकास रहा है। बढ़ती रक्षा कूटनीति और समुद्री सुरक्षा में हितों के सम्मिलन ने भारत-कोरिया सुरक्षा साझेदारी के दायरे को और बढ़ाया। इस संबंध में, सितंबर 2019 में भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की कोरिया यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच एक सैन्य रसद समझौते पर हस्ताक्षर समुद्री क्षेत्र में दोनों देशों के बीच हितों के बढ़ते सम्मिलन को रेखांकित करता है। तीसरा, एसएसपी विकास के तहत, विकास साझेदारी द्विपक्षीय संबंधों का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बन गया है। हालांकि कोरिया भारत के बुनियादी ढांचे के विकास में एक नया खिलाड़ी है इसके विकास के अनुभव और तकनीकी क्षमता को देखते हुए विकास साझेदारी की संभावना अधिक है। चौथा, भारत और कोरिया के बीच आर्थिक संबंधों में नई प्रगति देखी गई है। नई प्रगति में भारत में कोरियाई निवेश में वृद्धि, भारत-कोरिया संयुक्त उद्यमों की बढ़ती प्रवृत्ति और द्विपक्षीय व्यापार में सुधार शामिल हैं। पांचवीं प्रवृत्ति भारत-कोरिया संबंधों के लिए एक क्षेत्रीय आयाम का उदय है। क्षेत्रीय व्यवस्था के लिए एक साझा दृष्टिकोण और क्षेत्रीय मुद्दों पर साझेदारी के लिए समझौता, हिन्द-प्रशांत क्षेत्र में उभरती क्षेत्रीय सुरक्षा संरचना में नई दिल्ली और सियोल के बीच हितों के बढ़ते सम्मिलन को उजागर करता है। एसएसपी के तहत द्विपक्षीय संबंधों की छठी विशेषता दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को दृश्यता में सुधार और लोगों के बीच संबंधों को बढ़ावा देने के लिए मजबूत राजनीतिक प्रतिबद्धता पर जोर दिया गया है।

5. रणनीतिक साझेदारी प्रतिमान के तहत द्विपक्षीय संबंधों में विकास

जैसा कि पिछले खंडों में चर्चा की गई है, ऐतिहासिक, राजनीतिक और संस्थागत पहलुओं के साथ विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों का सार भी रणनीतिक साझेदारी प्रतिमान के तहत व्यापक और बहुआयामी बनने के लिए महत्वपूर्ण रूप से विकसित हुआ है। रणनीतिक साझेदारी के विकास की मैपिंग करते समय विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण विकास को पहले ही स्पष्ट किया जा चुका है; यह खंड रक्षा, आर्थिक और विकास साझेदारी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, संस्कृति और लोगों के बीच विनिमय पर केंद्रित एक विस्तृत चर्चा प्रदान करेगा।

रक्षा साझेदारी

भले ही भारत कोरियाई युद्ध में विरोधी की भूमिका में शामिल नहीं था लेकिन इसकी सेना दो प्रकार से शामिल थी- एक सैन्य चिकित्सा मिशन भेजकर मानवीय भूमिका और भारत के संरक्षक बल द्वारा शांति स्थापना की भूमिका।[58] जैसा कि शीत युद्ध की अवधि के दौरान भारत-कोरिया संबंधों की समग्र प्रवृत्ति में था, रक्षा सहयोग में बहुत कम विकास हुआ था। एकमात्र अपवाद 1980 के मध्यम में था जब दक्षिण कोरियाई कंपनी कोरिया टैकोमा ने भारतीय नौसेना के लिए पहली तीन सुकन्या श्रेणी की अपतटीय गश्ती नौकाओं का निर्माण किया। शीत युद्ध के बाद पहले दशक के दौरान, दोनों देशों ने मुख्य रूप से भारतीय और कोरियाई सशस्त्र बलों के अधिकारियों के बीच आदान-प्रदान के माध्यम से रक्षा सहयोग विकसित करने का प्रयास किया।

2000 के दशक के मध्य में रक्षा और सुरक्षा सहयोग में गति आई। एलईपी के दूसरे चरण के तहत भारत के पूर्वी एशियाई जुड़ाव के लिए एक प्रमुख अभियान रहा है। एक अन्य कारक पाकिस्तान और उत्तर कोरिया के बीच परमाणु और मिसाइल प्रौद्योगिकी के आदान-प्रदान के कारण कोरियाई प्रायद्वीप और भारतीय उपमहाद्वीप के बीच बढ़ता सुरक्षा संबंध रहा है।[59] इस संबंध में, कोरियाई विदेश मंत्री ली जोंग-बिन ने 2000 में अपनी नई दिल्ली यात्रा के दौरान कहा था कि, "भारत और दक्षिण कोरिया अब उपमहाद्वीप और कोरियाई प्रायद्वीप के बीच नए सुरक्षा संबंधों के प्रति पूरी तरह सचेत हैं। हाल के

वर्षों में, पाकिस्तान और उत्तर कोरिया के बीच परमाणु और मिसाइल सहयोग की परेशान करने वाली रिपोर्टें आई हैं"।[60] उन्होंने यह भी कहा कि सियोल और नई दिल्ली दोनों "हमारे संबंधित क्षेत्रों के बीच शांति और स्थिरता के पारस्परिक सुदृढ़ीकरण हेतु" सहयोग को मजबूत करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं।"[61]

दोनों देशों के बीच पहला द्विपक्षीय रक्षा वार्ता 2003 में और पहली विदेश नीति और सुरक्षा वार्ता 2005 में हुई थी। वर्ष 2005 में, दोनों देशों के रक्षा मंत्रालयों ने रक्षा उद्योग और रसद सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। समझौता ज्ञापन ने सचिव स्तर पर रक्षा उद्योग और रसद सहयोग (जेसीएम) के लिए संयुक्त समिति के संवाद रूपरेखा की स्थापना की। यह दीर्घकालिक रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने की दिशा में दोनों देशों के बीच हस्ताक्षरित पहला समझौता था। पहली जेसीएम 2007 में हुई थी। अब तक, सात जेसीएम हो चुकी हैं। बाद में दोनों पक्षों ने रक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए अतिरिक्त संस्थागत संवाद तंत्र भी स्थापित किए हैं। 2013 में उप मंत्री के स्तर पर स्थापित रक्षा नीति संवाद (डीपीडी) को रक्षा सचिव के स्तर पर अपग्रेड किया गया है और 2015 में दोनों पक्षों के बीच '2+2 वार्ता' का हिस्सा बनने के लिए शामिल किया गया है। संचालन समिति की बैठक (एससीएम) 2010 में स्थापित एक अन्य रक्षा संवाद तत्र है, जो भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ) और रक्षा अधिग्रहण कार्यक्रम प्रशासन (डीएपीए) और एजेंसी के बीच संयुक्त रक्षा अनुसंधान और विकास (आरएंडडी) एवं कोरिया का रक्षा विकास (एडीडी) पर ध्यान केंद्रित करता है। कोरिया के सात रक्षा सहयोग की संभावना को देखते हुए, भारत ने 2012 में एक स्थायी रक्षा सहकारी की संभावना को देखते हुए, रक्षा सहकारी को भेजकर सियोल में अपने दूतावास में एक रक्षा विंग बनाया। तब तक, कोरिया के साथ रक्षा मामलों को टोक्यो स्थित रक्षा सहकारी द्वारा नियंत्रित किया जाता था।[62]

रक्षा कूटनीति को उच्चतम स्तर पर रखते हुए दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी में गति को बनाए रखा गया है। वर्ष 2007 में कोरिया के रक्षा मंत्री के पहले भारतीय दौरे के दौरान दोनों देशों के बीच रक्षा मंत्रियों की पहली वार्ता का आयोजन किया गया था। वर्ष 2010 में, एके एंटनी, कोरिया का दौरा करने वाले पहले रक्षा मंत्री थे। तब से, 2015, 2017 और 2019 में, भारत के रक्षा मंत्रियों ने कोरिया का दौरा किया है। इसकी तुलना में 2018, 2020 और 2021 में कोरियाई राष्ट्रीय रक्षा मंत्रियों ने और रक्षा अधिग्रहण कार्यक्रम शासन के मंत्रियों ने 2016 और 2017 में भारत का दौरा किया। दोनों देशों के सैन्य बलों के प्रमुखों के दौरों से दोनों देशों के बीच रक्षा कूटनीति को आगे बढ़ाया गया।

रक्षा उद्योग में भागीदारी द्विपक्षीय रक्षा सहयोग का एक महत्वपूर्ण पहलू बन कर उभरा है। ऐसे में जबकि दोनों देश विभिन्न संवाद तंत्र के माध्यम से सहयोग किए जा सकने वाले उद्योगों एवं अनुसंधान और विकास के मौके तलाश रहे हैं, मेक इन इंडिया पहल के तहत भारत को रक्षा विनिर्माण केंद्र बनाने की मोदी सरकार के प्रयासों और रक्षा प्रणाली आपूर्तिकर्ताओं में विवधता लाने के प्रयासों ने कोरिया के साथ रक्षा साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए नया संदर्भ प्रदान किया है।[63] वैश्विक रक्षा बाज़ार में अपनी उपस्थिति बढ़ाने के लिए कोरिया का जोर, नए रक्षा साझीदारों के लिए भारत की तलाश को पूरा करता है।[64] भारत कोरिया को तीन कारणों से संभावित रक्षा साझेदार के रूप में देखता है; उन्नत तकनीकी क्षमता, न्यूनतम राजनीतिक जोखिम और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण पर कम सख्त नियमन।[65] उभरती हुई रक्षा औद्योगिक साझेदारी की एक महत्वपूर्ण विशेषता दोनों देशों के निजी क्षेत्र की भागीदारी है।

भारतीय सेना के लिए के-9 वज्र हॉवित्ज़र बनाने के लिए भारत की लार्सन एंड टुब्रो(एलएंडटी) और कोरिया की सैमसंग-टेकविन के बीच संयुक्त उद्यम उभरती हुई भारत-कोरिया रक्षा साझेदारी का एक उदाहरण है।[66] 700 मिलियन अमेरिकी डॉलर का अनुमानित संयुक्त उद्यम, रक्षा मंत्रालय द्वारा 'मेक इन इंडिया' पहल के तहत एक निजी कंपनी को दिए गए सबसे प्रमुख ऑर्डरों में से एक है। भारतीय सेना को उपलब्ध कराए गए 100 तोपों में से केवल दस का निर्यात कोरिया से किया गया था और बाकी के तोप भारत में बनाए गए थे। इस दिशा में एक और उपलब्धि है भारत के रक्षा मंत्रालय द्वारा अपनाए जाने योग्य पाया गया कोरिया में निर्मित बिहो स्वचालित विमानरोधी रक्षा प्रणाली। बिहो परियोजना को 'मेक इन इंडिया' में शामिल करने के लिए, कोरिया के ओईएम, एलआईजी नेक्स1 ने बिहो प्रणाली का उत्पादन और विपणन करने के लिए भारत के अडानी समूह के साथ मिलकर काम किया था।[67] के-9 वज्र और के-30 बिहो के निर्माण से जुड़ी दो साझेदारियों के अलावा, भारत की रिलायंस डिफेंस लिमि. ने भारत में सैन्य प्रणालियों के निर्माण के लिए एलआईजी नेक्स1 के साथ साझेदारी अनुबंध पर भी हस्ताक्षर किए।[68] हालांकि, 2020 में, भारत के रक्षा मंत्रालय ने घोषणा की कि उसने वायु रक्षा प्रणाली की खरीद संबंधी निविदा को रद्द कर दिया है।[69]

नौसेना जहाज निर्माण एक दूसरा क्षेत्र है जिसमें भारत और कोरिया साझेदारी की संभावना देखते हैं। इस संबंध में, जहाज निर्माण में रक्षा उद्योग सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर, अप्रैल 2017 में हस्ताक्षर किए गए थे।[70] यह भारतीय और कोरियाई जहाज निर्माण कंपनियों के बीच साझेदारी को सुविधाजनक बनाने के लिए दोनों सरकारों के बीच एक छात्र समझौता था। इस संबंध में, भारतीय नौसेना के लिए पांच फ्लीट सपोर्ट शिप बनाने के लिए भारत के हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड (एचएसएल) और कोरिया की हुंडई हेवी इंडस्ट्रीज के साथ मिलकर प्रयास किए गए। हालांकि, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और मूल्य में अंतर के कारण, परियोजना शुरू नहीं हो सकी।[71] भारतीय नौसेना के लिए 12 माइन्स्वीपर्स (सुरंग भेदी पोत) बनाने के लिए भारत के गोवा शिपयार्ड और कोरिया के कंगनाम कॉर्पोरेशन के बीच भी इसी प्रकार का प्रयास किया गया था।[72] कोरिया देवू शिपबिल्डिंग एंड मरीन इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट पी 75 (I) के तहत भारतीय नौसेना के लिए छह पारंपरिक पनडुब्बियों के निर्माण का एक प्रमुख दावेदार है।[73]

रक्षा उद्योग की साझेदारी को और आगे ले जाने के लिए, नई दिल्ली और सियोल ने कोरियाई रक्षा मंत्री की भारत के दौरे के दौरान 2020 में 'रक्षा उद्योग सहयोग के लिए रोडमैप' को अंतिम रूप दिया।[74] रक्षा सहयोग रोडमैप के आदान-प्रदान का विचार पहली बार फरवरी 2019 में राष्ट्रपति मून जे-इन के साथ बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा प्रस्तावित किया गया था। रोडमैप में रक्षा संबंधों को और बेहतर बनाने की परिकल्पना की गई है जो परंपरागत क्रेता-विक्रेता मॉडल से सह-उत्पादन और सह-विकास पर केंद्रित है। इस संबंध में, यह सहयोग के संभावित क्षेत्रों को सूचीबद्ध करता है, जिसमें भूमि प्रणालियां (लैंड सिस्टम्स), नौसेना प्रणालियां (नेवल सिस्टम्स), वायु प्रणालियां (एयरो सिस्टम्स) और नियंत्रित हथियार प्रणालियां (गाइडेड वेपन सिस्टम्स) शामिल हैं। यह अनुसंधान और विकास, परीक्षण, प्रमाणन, गुणवत्ता आश्वासन और विपणन के माध्यम से रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने को भी आशा करता है। मेक इन इंडिया प्रारूप के साथ दोनों देशों की सरकारी और निजी रक्षा कंपनियों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत-कोरिया रोडमैप तैयार किया गया है। इस संबंध में, 2021 में रक्षा मंत्रियों के बीच नई दिल्ली में हुई बैठक के दौरान, अनुबंध के कार्यान्वयन के लिए एक टास्कफोर्स प्रभारी बनाने पर सहमति हुई।[75] रोडमैप में उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में नवस्थापित औद्योगिक गलियारों में कोरियाई निवेश को बढ़ावा देने की भी परिकल्पना की गई है।[76]

जैसा कि पहले के खंड में चर्चा की गई है, भारत-कोरिया रक्षा सहयोग में समुद्री सुरक्षा प्रमुख स्थान रखता है। सितंबर 2019 में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की कोरिया यात्रा के दौरान दोनों देसों के बीच सैन्य रसद समझौते पर हस्ताक्षर, समुद्री सुरक्षा में दोनों देशों के बीच बढ़ते हितों के सम्मिलन को रेखांकित करता है। यह अनुबंध दोनों नौसेनाओं को ईंधन भरने और रख-रखाव के लिए एक-दूसरे के ठिकानों के उपयोग के माध्यम से अपनी परिचालन क्षमता का विस्तार करने और दोनों नौसेनाओं के बीच अंतर-संचालन क्षमता बढ़ाने में मदद मिलेगी।[77] दो नौसैनिक बलों के बीच संयुक्त अभ्यास और नियमित पोर्ट कॉल दौरों के जरिए समुद्री सुरक्षा सहयोग को बढ़ाया गया है। दोनों नौसेनाओं ने नवीनतम संयुक्त अभ्यास 2017 में, मुंबई के तट पर किया था। इसके अलावा, पिछले पांच वर्षों में भारतीय नौसेना के पांच पोत कोरिया गए जिससे दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग का विस्तार हुआ है। भारतीय नौसेना के अनुसार, ये दौरे, "भारत की 'एक्ट ईस्ट' पॉलिसी और सुरक्षा एवं स्थिरता हेतु भारतीय नौसेना और आरओके नौसेना के बीच समुद्री सहयोग को बढ़ाने के लिए भारतीय नौसेना के बढ़ते कार्यों और संचालन पहुंच को दिखाना था।"[78] भारतीय और कोरिया तटरक्षक बल के बीच बढ़ते सहयोग के माध्यम से समुद्री सुरक्षा सहयोग में विकास भी दिखता है। वर्ष 2006 में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के बाद से, दोनों तट रक्षक बल नियमित रूप से संयुक्त अभ्यास कर रहे हैं। अप्रैल 2018 में, हिन्द महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा में सुधार हेतु चेन्नई के पास 'सहयोग-ह्योब्ल्ययोग 2018' नाम से द्विपक्षीय तटरक्षक बल अभ्यास का आयोजन किया गया था। यह संयुक्त अभ्यास का उन्नत संस्करण था।

आर्थिक संबंध

आर्थिक संबंध भारत-कोरिया संबंधों का मुख्य स्तंभ बने रहे। वर्ष 2009 में सीईपीए पर हस्ताक्षर, दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों में एक महत्वपूर्ण घटना थी। सीईपीए में वस्तुएं, सेवाएं, निवेश, द्विपक्षीय सहयोग, बौद्धिक संपदा अधिकार और प्रतिस्पर्धा शामिल है। दोनों देशों द्वारा अनुसमर्थन के बाद यह 2010 में लागू हुआ। सीईपीए के बाद पहले ही वर्ष में द्विपक्षीय व्यापार 40 प्रतिशत बढ़कर, वर्ष 2009 के 12 अरब डॉलर से बढ़कर 2010 में 17 अरब डॉलर हो गया और 2013 में दो-तरफा व्यापार लगभग 20.5 अरब डॉलर था। हालांकि, द्विपक्षीय व्यापार में 2012 के बाद से गिरावट आई है, 2016 में केवल 15.8 अरब डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार हुआ था, जिसके बाद इसमें सुधार हुआ और 2018 में यह 21.5 अरब डॉलर तक पहुंच गया।[79]

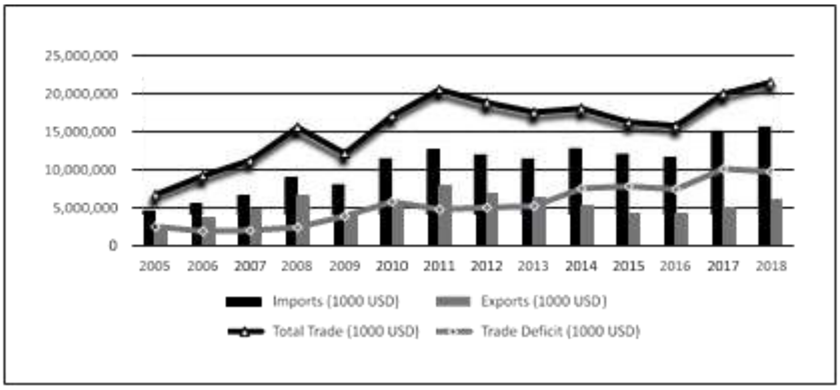

चित्रः1 भारत- कोरिया व्यापार

(स्रोतः कोरिया इंटरनेशनल ट्रेड एसोसिएशन)

सीईपीए के लागू होने के बाद से बढ़ता हुआ व्यापार घाटा भारतीय दृष्टिकोण से चिंता का विषय रहा है। जैसे- जैसे द्विपक्षीय व्यापार बढ़ा, घाटा भी बढ़ता गया, 2010 में यह 5 अरब डॉलर का था, 2016 में 7.4 अरब डॉलर का और 2017 में यह 10.6 अरब डॉलर तक पहुंच गया। सीईपीए उन्नयन वार्ता के दौरान, भारत ने भारतीय निर्यात के अनुरूप लाभ सुनिश्चित करने के लिए समझौते के बेहतर कार्यान्वयन की मांग की। इस दिशा में, भारत ने फार्मास्युटिकल्स, कृषि संबंधी वस्तुएं और आईटी सेवाओं के लिए बेहतर बाज़ार पहुंच पर ज़ोर दिया।

चिंता का एक अन्य क्षेत्र भारत का एक्सपोर्ट बास्केट है (देकें परिशिष्ट 1)। कार्यान्वयन के दस वर्षों के बाद भी, कोरिया को भारतीय निर्यात में मुख्य रूप से प्राथमिक सामग्रियों और माध्यमिक वस्तुएं शामिल हैं, जबकि यह ज्यादातर उच्च मूल्य वाली वास्तुओं का आयात करता है। यह न केवल भारत-कोरिया द्विपक्षीय व्यापार के लिए एक समस्या है बल्कि भारत के समग्र व्यापार से जुड़ा बड़ा मुद्दा है। हालांकि, भारत-कोरिया व्यापार के बारे में दिलचस्प बात यह है कि तैयार माल की कुछ श्रेणियों के लिए भारत कोरिया से आयात करता है, यह उसी श्रेणी की वस्तुओं के लिए कच्चा माल का निर्यात करता है। ऐसी श्रेणियों में उत्पाद बनाने के लिए भारत में कोरियाई निवेश को प्रोत्साहित करना व्यापार घाटे के मुद्दे और भारतीय निर्यात की कम उन्नत प्रोडक्ट बास्केट को संबोधित करने का एक तरीका है।[80]

सीईपीए में ठहराव और उसके कम उपयोग को देखते हुए, भारतीय और कोरियाई नेताओं ने 2015 में सीईपीए को अपग्रेड करने पर सहमत हुए। सीईपीए के उन्नयन की प्रक्रिया को जारी रखने पर सहमति जताते हुए, 2018 में राष्ट्रपति मून के दौरे के दौरान 'अर्ली हार्वेस्ट पैकेज' के अंतरिम समझौते की घोषणा की गई थी। दोनों देशों ने 2030 तक 50 अरब डॉलर के द्विपक्षीय व्यापार को प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया था।

अर्ली हार्वेस्ट पैकेज में, कोरिया ने अपने बाज़ार में 17 भारतीय उत्पादों को निःशुल्क अभिगम देने पर सहमति जताई जबकि कोरिया के 11 उत्पादों को भारतीय बाज़ार में ऐसा ही अभिगम दिए जाने की बात है। कोरिया के बाज़ार में भारतीय आम, बीयर, पॉपकॉर्न, मक्का और उससे बने उत्पाद, जेली और जैम को, ज़ीरो मार्केट एक्सेस यानि ये उत्पाद कोरिया के बाज़ार में नहीं बेचे जा सकते। पैकेज में इस बात पर भी सहमति बनी कि भारत योग प्रशिक्षक भेज सकता है और भारतीय योग संस्थानों को कोरिया में प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने की अनुमति दी जाएगी। भारत में ताइक्वांडो को बढ़ावा देने के लिए कोरिया को इसी तरह की रियायतें दी जाती हैं।[81]

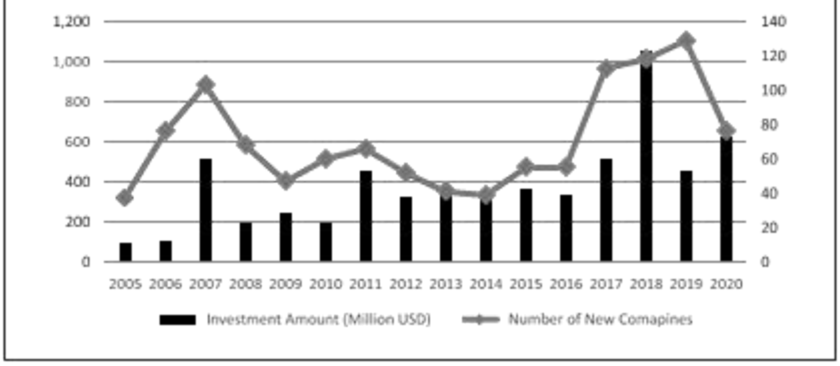

चित्र 2: भारत में कोरिया का निवेश

(स्रोतः एक्ज़िम बैंक, कोरिया गणराज्य)

भारत सरकार के निवेश संवर्धन विभाग के अनुसार, 2000-2021 की अवधि में, 4.89 अरब अमेरिकी डॉलर के संचयी एफडीआई के साथ, कोरिया भारत में निवेश करने वाला 13वां सबसे बड़ा निवेशक देश के रूप में उभरा था।[82] कोरियन एक्ज़िम बैंक के आंकड़ों के अनुसार, इस अवधि में कुल 6.3 अरब डॉलर का कोरियाई निवेश किया गया है।[83] कोरियाई निवेश के लिए भारत और कोरिया के आंकड़ों में अंतर अन्य देशों मुख्य रूप से सिंगापुर, के कारण है। यदि भारत में पहले से ही काम कर रही कोरियाई कंपनियों के पुनर्निवेश आंकड़ों को भी शामिल कर लें तो कोरिया द्वारा किए जाने वाले वास्तविक निवेश के आंकड़े कहीं अधिक होंगे। भारत में कोरिया का कुल निवेश विश्वभर में इसके द्वारा किए जाने वाले कुल निवेश का केवल 1.24 प्रतिशत है।

विनिर्माण के क्षेत्र में लगभग 84 प्रतिशत, थोक और खुदरा व्यापार में लगभग 7 प्रतिशत और बीमा के क्षेत्र में लगभग 4 प्रतिशत कोरियाई निवेश किया जाता है। कोरिया की लगभग 800 कंपनियां हैं जो भारत में कारोबार करती हैं। कोरिया में भारत द्वारा लगभग 1 अरब डॉलर निवेश किए जाने का अनुमान था। कोरिया में प्रमुख भारतीय निवेश में शामिल हैं- 2004 में टाटा मोटर्स द्वारा 102 मिलियन डॉलर की लागत से देवू कमर्शल व्हीकल कंपनी का अधिग्रहण, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड की सहायक कंपनी नोवेलिस इंक ने 2005 में नोवेलिस कोरिया लिमिटेड में 600 मिलियन डॉलर का पूंजी निवेश; महिन्द्रा एंड महिन्द्रा (एमएंडएम) ने 458 मिलियन डॉलर के निवेश के साथ सांगयोंग मोटर्स में 70प्रतिशत हिस्सेदारी ली थी। हालांकि, 2010 में महिन्द्रा एंड महिन्द्रा द्वारा सांगयोंग के अधिग्रहण के बाद से किसी बड़ी भारतीय कंपनी ने कोरिया में निवेश नहीं किया है।[84]

हाल ही में भारत में कोरियाई निवेश की नई परियोजनाओं की घोषणाओं के साथ वृद्धि का रुझान देखा जा रहा है।[85] नई दक्षिणी नीति के तहत कोरिया की आर्थिक विवधीकरण रणनीति निवेश की इस नई लहर को सुगम बनाने वाला प्रमुख कारक है।[86] भारत-कोरिया आर्थिक संबंधों में एक और महत्वपूर्ण विकास भारतीय और कोरियाई कंपनियों के बीच भारत में संयुक्त उद्यमों की सकारात्मक प्रवृत्ति है। यह एक महत्वपूर्ण विकास है क्योंकि भारत में कोरियाई निवेश का प्रमुख मॉडल अब तक पूर्ण स्वामित्व वाले उद्यमों के रूप में ही रहा है।[85]

निवेश और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए नई दिल्ली और सियोल ने कई कदम उठाए हैं। वर्ष 2014 में राष्ट्रपति पार्क के भारत दौरे के दौरान, दोनों पक्ष सीईओ फोरम बनाने पर सहमत हुए थे। इस फोरम के लिए, दोनों सरकारों के बीच आर्थिक सहयोग को और कैसे बढ़ाया जा सकता है, पर, रिपोर्ट देना अनिवार्य बनाया गया था। दोनों देश वर्तमान 'भारत-आरओके संयुक्त निवेश संवर्धन समिति' के विस्तारित और पुनर्गठित प्रतिस्थापन के रूप में कैबिनेट स्तर पर 'भारत-आरओके संयुक्त व्यापार और निवेश संवर्धन समिति' बनाने पर सहमत हुए हैं। उन्होंने बैंगलोर में कोरिया ट्रेड- इनवेस्टमेंट प्रोमोशन एजेंसी (केओटीआरए) कार्यालय और नई दिल्ली में कोरिया इंटरनेशनल ट्रेड एसोसिएशन (केआईटीए) कार्यालय खोलने का भी स्वागत किया है, आशा है कि ये कार्यालय दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश का विस्तार करने के लिए काम करेंगें।

भारत में कोरियाई निवेश को बढ़ावा देने के लिए नई दिल्ली में वाणिज्य मंत्रालय के तहत जून 2016 में 'कोरिया प्लस' नामक एक नया तंत्र शुरू किया गया था। अपने संचालन के पहले दो वर्षों में 'कोरिया प्लस' ने 100 से अधिक कोरियाई निवेशों को भारत लाने में मदद की।[88] चौथे औद्योगिक क्रांति के लाभों का उपयोग करने के लिए भविष्य की प्रौद्योगिकियों में सहयोग को बढ़ावा देने हेतु दोनों देशों के वाणिज्य, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालयों से जुड़े द्विपक्षीय तंत्र 'फ्यूचर स्ट्रैटेजी ग्रुप' को 2018 में लॉन्च किया गया था।[89] स्मार्ट सिटी, हरित प्रौद्योगिकी (ग्रीन टेक्नोलॉजी), कृत्रिम बुद्धिमत्ता (आर्टिफिशल इंटेलिजेंस), आईओटी समेत भविष्य की तकनीक के क्षेत्रों में संयुक्त रूप से वित्त पोषित परियोजनाओं की पहचान करना और उन्हें आरंभ करना

अनिवार्य है। वाणिज्यिक संबंधों को सुविधाजनक बनाने के लिए भारत-कोरिया सीईओ फोरम और भारत-कोरिया व्यापार शिखर सम्मेलन भी शुरू किया गया। इसके अलावा, 2019 में प्रधानमंत्री मोदी के कोरिया दौरे के दौरान, संयुक्त नवाचार को सुगम बनाने के लिए भारत- कोरिया स्टार्ट-अप इकोसिस्टम को करीब लाने हेतु भारत-कोरिया स्टार्ट-अप हब की स्थापना की घोषणा की गई थी। जुलाई 2018 में केओटीआरए और इन्वेस्ट इंडिया के बीच समझौता होने के बाद स्टार्ट-अब हब बना था।

आर्थिक संबंधों का एक अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्र जिसने गति पकड़ी है, वह है, भारतीय बुनियादी ढांचे और विकास परियोजानाओं में कोरिया की भागीदारी। इस संबंध में, एक्सपोर्ट- इम्पोर्ट बैंक ऑफ कोरिया (के-एक्ज़िम) और इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमि. (आईआईएफसीएल) ने बुनियादी ढांचा में वित्तपोषण हेतु आपसी सहयोग को मजबूत बनाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। दोनों संस्थानों के बीच समझौता ज्ञापन भारतीय बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के संबंध में सूचना साझा करने और सह-वित्तपोषण की सुविधा प्रदान करेगा और इससे कोरिया की कंपनियों के लिए ऐसी परियोजनाओं का हिस्सा बनने के अवसरों के बढ़ने की संभावना है। इससे पहले अप्रैल 2008 में, कोरिया एक्ज़िमबैंक और आईआईएफसीएल ने 4.26 अरब डॉलर का कोयले से चलने वाले मुंद्रा संयंत्र परियोजना का सफलतापूर्वक सह-वित्तपोषण किया था। इस समझौते ने आईआईएफसीएल के साथ दीर्घकालिक संबंध स्थापित कर भारत की बुनियादी ढांचा बाज़ार में कोरियाई कंपनियों के प्रवेश की नींव रखी और कोरियाई कंपनियों को भारत में अनुबंध प्राप्त करने के लिए पहले से अधिक अनुकूल स्थिति में बनाई। मोदी और पार्क के नेतृत्व में द्विपक्षीय संबंधों को जो विशेष गति मिली वह समुद्री सहयोग में स्पष्ट रूप से दिखती है। भारत और कोरिया के बीच मेक इन इंडिया पहल के प्रमुख क्षेत्र के रूप में समुद्र क्षेत्र को माना जा रहा है। भारत के समुद्री क्षेत्र को बढ़ावा देने के प्रयास में, भारत सरकार ने अप्रैल 2016 में मुंबई में पहला समुद्री शिखर सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें कोरिया एकमात्र साझीदार था। शिखर सम्मेलन में बंदरगाह-नीत विकास, जहाज निर्माण, जहाज की मरम्मत और जहाज पुनर्चक्रण, शिपिंग और रसद, भीतरी प्रदेशों की कनेक्टिविटी, अंतर्देशीय जल परिवहन, हरित ऊर्जा, सुरक्षा, शिक्षा और प्रशिक्षण, वित्त पोषण, द्वीप विकास, क्रूज़ और लाइटहाउस पर्यटन, समुद्री भोजन और जलीय कृषि में प्रचार और निवेश पर केंद्रित था। शिखर सम्मेलन में समुद्र और मत्स्य पालन मंत्री किम यंग-सुक के नेतृत्व में कोरिया की 50 से अधिक कंपनियों और 200 से अधिक प्रतिनिधियों के प्रतिनिधिमंडल ने कोरिया का प्रतिनिधित्व किया था। शिखर सम्मेलन के दौरान, भारत और कोरिया ने विकासशील बंदरगाहों में सहयोग और पारस्परिक सहायता के लिए एक समझौता भी किया था।

वर्ष 2015 में प्रधानमंत्री मोदी की कोरिया यात्रा के दौरान, भारत में बुनियादी ढांचे के विकास को सहयोग के अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में देखा गया था। कोरिया ने बुनियादी ढांचा विकास के लिए 10 अरब डॉलर के वित्तीय पैकेज की घोषणा की थी। प्रस्ताव को बाद में कोरियाई आर्थिक विकास सहयोग कोष (ईडीसीएफ) से 1 अरब डॉलर की आधिकारिक विकास सहायता (ओडीए) और कोरिया एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट बैंक (केएक्ज़िम) से 9 अरब डॉलक के रियायती ऋण के रूप में पुनर्पैकेज किया गया। जून 2017 में भारतीय वित्त मंत्री अरुण जेटली की कोरिया दौरे के दौरान इस संबंध में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया था।[90] कोरियाई ओडीए स्वीकार करने के लिए भारत ने अपने ओडीए कानून में संशोधन किया जो पहले केवल जी7 देशों से द्विपक्षीय सहायता की स्वीकृति तक सीमित था।

सितंबर 2017 में, यह घोषणा की गई थी कि फंड का उपयोग महाराष्ट्र राज्य के तीन मेगा बुनियादी ढांचा परियोजनाओं; नागपुर-मुंबई सुपर कम्युनिकेशन एक्सप्रेसवे (एनएमएसई), कल्याण- डोम्बिवली स्मार्ट सिटी और बांद्रा गवर्नमेंट कॉलोनी पुनर्विकास, में किया जाएगा।[91] इस संबंध में, महाराष्ट्र राज्य सरकार और कोरिया के

भूमि, परिवहन और समुद्री मामलों के मंत्री ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया था।[92] कोरिया की निर्माण कंपनी कोरिया एक्सप्रेसवे कॉरपोरेशन (केईसी) और महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम (एमएसडीआरसी) ने बाद में विशेष रूप से नागपुर-मुंबई एक्सप्रेसवे परियोजना के कार्यान्वयन हेतु एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया था। कल्याण-डोम्बिवली स्मार्ट सिटी परियोजना के निर्माण में सहयोग हेतु कोरिया के भूमि और आवास निगम (एलएच) एवं कल्याण-डोम्बिवली निगम के बीच एक अन्य समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया।[93]

वर्ष 2015 के सागरमाला पहल के तहत परिकल्पित आर्थिक विकास के संभावित स्रोत के रूप में भारत की विशाल तटीय क्षेत्र के उपयोग करने के उद्देश्य से बंदरगाह विकास, जहाज निर्माण, परिवहन और रसद पर केंद्रित समुद्री क्षेत्र, विशेष रणनीतिक साझेदारी के तहत द्विपक्षीय सहयोग के आशाजनक क्षेत्र के रूप में उभरा है। वर्ष 2016 में पहले भारत समुद्री शिखर सम्मेलन के लिए साझीदार देश के रूप में कोरिया का चयन समुद्री क्षेत्र में द्विपक्षीय साझेदारी बनाने पर भारत के जोर को दर्शाता है।[94] इस दिशा में अप्रैल 2016 में बंदरगाह विकास में आपसी सहायता पर एक द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किया गया था।[95] समझौते का उद्देश्य अन्य क्षेत्रों के साथ-साथ बंदरगाह विकास और संचालन में प्रौद्योगिकी एवं अनुभवों को साझा करना और बंदरगाह से संबंधित निर्माण, आपसी हित के भवन और इंजीनियरिंग परियोजनाओं में संचालन और संयुक्त भागीदारी समेत अन्य क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देना था।[96]

अप्रैल 2018 में, भारत और कोरिया ने नाविकों के योग्यता प्रमाणपत्रों की पारस्परिक मान्यता पर एक समझौता किया था जिससे भारतीय नाविकों के लिए 500 से अधिक कोरियाई जहाजों पर नौकरी प्राप्त करने का रास्ता खुला।[97] रेल और सड़क आधारभूत ढांचा भी द्विपक्षीय साझेदारी के संभावित क्षेत्रों के रूप में उभर रहे हैं। वर्ष 2018 में राष्ट्रपति मून के भारत दौरे के दौरान भारत के अनुसंधान अभिकल्प एवं मानक संगठन (आरडीएसओ) और कोरिया रेलरोड रिसर्च इंस्टीट्यूट (केआरआरआई) के बीच अनुबंध, रेलवे अनुसंधान और रेलवे से संबंधित अनुभव एवं रेलवे के विकास के आदान-प्रदान में सहयोग का पता लगाने के लिए किया गया है। यह संयुक्त अनुसंधान परियोजनाओं की भी परिकल्पना करता है, जिसमें भारत में उन्नत रेलवे अनुसंधान और विकास सुविधा स्थापित करना और एक कोरियाई मॉडल हाई-स्पीड ट्रेन की व्यवहार्यता का अध्ययन करना शामिल है। इसके अलावा, भारत में सड़क और परिवहन बुनियादी ढ़ाचे के विकास में सहयोग को बढ़ावा देने और तकनीकी अनुभव का आदान-प्रदान करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और कोरिया के एक्सप्रेस वे सहयोग के बीच 2019 में प्रधानमंत्री मोदी की कोरिया यात्रा के दौरान एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी (एसएंडटी) में साझेदारी

विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग भारत-कोरिया रणनीतिक साझेदारी का एक महत्वपूर्ण एजेंडा बनकर उभरा है। सहयोग के संभावित क्षेत्रों का पता लगाने का प्रयास 2005 में सियोल में भारत- आरओके संयुक्त एसएंडटी समिति की पहली बैठक के साथ आरंभ हुआ। बैठक में दोनों पक्षों के बीच सहयोग हेतु जैव प्रौद्योगिकी, नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी एवं सूचना तकनीक में विशिष्ट परियोजना प्रस्तावों की पहचान की गई। इस संबंध में, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग और कोरिया इंडस्ट्रीयल टेक्नोलॉजी फाउंडेशन (केओटीईएफ) के बीच वैज्ञानिक एवं तकनीकी सहयोग पर समझौता किया गया। इसके अलावा, 2006 में भारत के राष्ट्रपति अब्दुल कलाम के कोरिया दौरे के दौरान एसएंडटी सहयोग पर बहुत जोर दिया गया। दौरे के दौरान, भारत-कोरिया ने 1976 में दोनों देशों के बीच एसएंडटी सहयोग हेतु हस्ताक्षरित रूपरेखा समझौता को संशोधित किया गया। जनवरी 2010 में भारत के दौरे पर आए राष्ट्रति ली म्युंग-बाक के दौरे के दौरान एसएंडटी में सहयोग

चर्चा का एक महत्वपूर्ण एजेंडा रहा है। एसएंडटी सहयोग के महत्व को स्वीकार करते हुए संयुक्त बयान ने संयुक्त अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए 10 मिलियन डॉलर (प्रत्येक पक्ष 5 मिलियन डॉलर का योगदान करता) का एक समर्पित कोष बनाने पर विचार करने हेतु वित्रान और प्रौद्योगिकी पर संयुक्त समिति के निर्णय का समर्थन किया। शिखर सम्मेलन की बैठक के दौरान, दोनों पक्षों ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए तीन समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए; सूचना प्रौद्योगिकी एवं सेवाओं पर समझौता, 2010-2012 की अवधि के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग के कार्यक्रम पर समझौता और बाह्य अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग में सहयोग के लिए समझौता। बैठक के दौरान, एसएंडटी पर संयुक्त समिति को मंत्रिस्तरीय स्तर पर अपग्रेड करने का भी प्रस्ताव दिया गया था।[98] पहला संयुक्त मंत्रिस्तरीय एसएंडटी 2011 में आयोजित किया गया था। अब तक, संयुक्त मंत्रिस्तरीय एसएंडटी समिति की चार बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं, अंतिम बैठक 2018 में हुई थी।

वर्ष 2012 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सियोल यात्रा के दौरान भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) और केएआरए के बीच सहयोग पर समझौता किया गया था। अन्य बातों के अलावा, समझौता ज्ञापन में भारत से कोरियाई उपग्रहों को लॉन्च करने का पता लगाने का प्रावधान था।[99] वर्ष 2011 भारत और कोरिया ने कोरिया- भारत संयुक्त विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी अनुसंधान कोष की स्थापना की और इसका उपयोग संयुक्त अनुसंधान परियोजनाओं, मानव संसाधन आदान-प्रदान, कार्यशालाओं और अन्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सहयोग कार्यक्रमों के लिए किया। इसने 2006 में राष्ट्रपति अब्दुल कलाम द्वारा अपनी कोरिया यात्रा के दौरान प्रस्तावित द्विपक्षीय एसएंडटी प्रौद्योगिकी सहयोग रूपरेखा- ग्लोबल नॉलेज प्लेटफॉर्म (जीकेपी) प्रोजेक्ट को शुरू करने में भी मदद की। जीकेपी पहल ने दोनों देशों के प्रतिनिधिक विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संस्थानों और व्यवसायों को ब्रॉडबैंड इंटरनेट के माध्यम से महंगे उपकरणों के दूरस्थ उपयोग, ऑनलाइन व्याख्यान, संयुक्त अनुसंधान, सहयोगी डिजाइन, उत्पादों के सह-निर्माण आदि के सफल उपयोग को एक दूसरे से जोड़ने की परिकल्पना की। वर्ष 2014 में, संयुक्त आरएंडडी फंड (अनुसंधान और विकास कोष) के सफल उपयोग के बाद, इसी वर्ष प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और राष्ट्रपति पार्क गुएन- हे के बीच शिखर सम्मेलन के दौरान, दोनों पक्षों ने 10 मिलियन डॉलर का एक अतिरिक्त संयुक्त कोष बनाने पर सहमति व्यक्त की गई (इस कोष में दोनों देश 5 मिलियन डॉलर का योगदान करेंगे) ताकि उद्योगों, शिक्षाविद् और संस्थानों द्वारा संयुक्त रूप से संचालित की जाने वाली मेगा परियोजनाओं को बढ़ावा दिया जा सके।[100]

प्रधानमंत्री सिंह और राष्ट्रपति पार्क के बीच शिखर सम्मेलन के दौरान, दोनों सरकारें भारत-आरओके आईसीटी पॉलिसी फोरम बनाने पर भी सहमत हुईं। राष्ट्रपति पार्क के दौरे के दौरान हस्ताक्षर किए गए नौ अनुबंधों में से पांच एसएंडटी सहयोग पर थे।[101] हस्ताक्षर किए गए समझौतों में आईसीटी क्षेत्र में सहयोग पर संयुक्त घोषणा के साथ-साथ सॉफ्टवेयर उद्योग के विकास के लिए द्विपक्षीय सहयोग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एक संयुक्त अनुप्रयुक्त अनुसंधान और विकास कार्यक्रम एवं बाह्य अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग में सहयोग हेतु भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन और कोरिया एयरोस्पेस अनुसंधान संस्थान के बीच अनुबंध के कार्यान्वयन हेतु भारत के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय और कोरिया के विज्ञान, आईसीटी एवं भविष्य योजना मंत्रालय के बीच विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के बीच समझौता किया गया। वर्ष 2015 में प्रधानमंत्री मोदी की कोरिया यात्रा के दौरान अंतरिक्ष अनुसंधान में सहयोग को और बढ़ावा मिला। शिखर सम्मेलन के दौरान, दोनों पक्षों ने डीप स्पेस क्रॉस ट्रैकिंग और संचार के क्षेत्रों में सहयोग के ठोस तरीके को मजबूत करने के लिए इसरो और केएआरआई के बीच नियमित रूप से कार्य-स्तरीय वार्ता आयोजित करने, चंद्रयान-1 द्वारा जुटाए गए आंकड़ों

को साझा करने, अंतरिक्ष विज्ञान और उसके अनुप्रयोग के क्षेत्र में गगन-केएएसएस इंटरऑपरेबिलिटी और तकनीकी सहयोग पर सहमति व्यक्त की।[102]

वर्ष 2018 में चौथी संयुक्त समिति की बैठक के दौरान, भारत और कोरिया विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सहयोग को और बढ़ावा देने के लिए दो प्रक्रिया स्थापित करने पर सहमत हुए। इन पहलों की घोषणा 2018 में फ्यूचर स्ट्रैटेजिक ग्रुप और इंडो-कोरियन सेंटर फॉर रिसर्च एंड इनोवेशन (आईकेसीआरआई) के बीच शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मून की उपस्थिति में की गई थी। आईकेसीआरआई की परिकल्पना नवाचार और उद्यमिता एवं प्रौद्योगिकी हस्तांतरण समेत दोनों देशों के बीच अनुसंधान एवं नवाचार में सभी सहकारी कार्यक्रमों के नियमित संचालन और प्रबंधन के केंद्र के रूप में की गई है। मार्च 2021 में आईकेसीआरआई की शाखा दिल्ली में खोली गई थी।

अनुसंधान और विकास सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए भारत के ग्लोबल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी एलायंस (जीआईटीए) ने कोरिया इंस्टीट्यूट फॉर एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी (केआईएटी) के साथ मिलकर काम किया था। 2018 में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के बाद से, केआईएटी और जीआईटीए संयुक्त अनुसंधान एवं विकास (आरएंडडी) को बढ़ावा देने के मौके ढूंढ़ रहा है। इस संबंध में, उन्होंने उन्नत विनिर्माण, ऊर्जा, आईसीटी और स्वास्थ्य देखभाल के क्षेत्र में, भारतीय एवं कोरियाई विश्वविद्यालयों, कंपनियों एवं अनुसंधान संस्थानों को शामिल करते हुए, चार परियोजनाओं की पहचान की है।[103]

ऐसे में जबकि भारत-कोरिया एसएंडटी सहयोग का जोर संयुक्त अनुसंधान, विद्वानों के आदान-प्रदान एवं क्षमता निर्माण को बढ़ावा देने के लिए राज्य के नेतृत्व वाली पहल पर रहा है, अनुसंधान संस्थानों एवं निजी कंपनियों, विशेष रूप से भारत में सक्रिय कोरियाई समूह की भूमिका पर विचार करना भी महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए सैमसंग ने 1996 में बेंगलुरु में अपना पहला अनुसंधान और विकास केंद्र खोला था। वर्तमान में, भारत में सैमसंग के पांच आरएंडडी केंद्र हैं, जिसमें हजारों भारतीय शोधकर्ता और इंजीनियर कार्यरत हैं। इसी प्रकार, एलजी और हुंडई की भी भारत में अपनी अनुसंधान इकाईयां हैं।[104]

पिछले कुछ वर्षों में भारतीय और कोरियाई विश्वविद्यालयों के बीच सहयोग भी बढ़ा है जबकि विश्वविद्यालय में सहयोग के विकास और संस्थागत स्तर पर अनुसंधान को ट्रैक करना कठिन है, भारत- कोरिया विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी केंद्र (आईकेएसटी) की स्थापना दोनों देशों के अनुसंधान संस्थानों के बीच बढ़ते विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहयोग को दर्शाती है।[105] कोरिया इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी (केआईएसटी) ने 2010 में भारतीय विज्ञान संस्थान, बैंगलोर में, भारत और कोरिया के विभिन्न विश्वविद्यालयों/ संस्थानों के सहयोग से, मुख्य रूप से प्रौद्योगिकी एवं व्यावसायिक साझेदारियों को बढ़ावा देने के लिए, भारत-कोरिया विज्ञान और प्रौद्योगिकी केंद्र (आईकेएसटी) की स्थापना की थी। आईकेएसटी ने संयुक्त अनुसंधान और शोधकर्ता गतिशीलता समेत द्विपक्षीय एसएंडटी सहयोग हेतु प्रमुख आधार बनने की परिकल्पना की है। आईकेएसटी के तत्वाधान में दो देशों के बीच संयुक्त सहयोगी अनुसंधान का मुख्य फोकस ऊर्जा, पर्यावरण, जल, सामग्रियां, रोबोटिक्स और कम्प्यूटेशनल साइंस हैं।

संस्कृति और लोगों के बीच आपसी संपर्क

जैसा कि पहले चर्चा की गई थी, द्विपक्षीय संबंधों के अन्य आयामों के साथ-साथ सांस्कृतिक और लोगों के बीच आपसी संबंधों पर भी रणनीतिक साझेदारी प्रतिमान के तहत अधिक ध्यान दिया गया है। ऐसे में जबकि कोरियाई लहर[106] के जरिए सांस्कृतिक वैश्वीकरण की घटना और भारतीय सांस्कृतिक उत्पादों की बढ़ती

लोकप्रियता से दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक संपर्क का संदर्भ बढ़ा है, भारत और कोरिया ने भी एक दूसरे के इतिहास और संस्कृति के बारे में और लोगों के बीच आपसी संपर्क हेतु अधिक अवसर पैदा करने के लिए पहल की है। वर्ष 2010 में रणनीतिक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर करने के दौरान, नई दिल्ली और सियोल ने 2011 को 'कोरिया में भारत वर्ष' और 'भारत में कोरिया वर्ष' के रूप में घोषित किया और दोनों देशों में कई प्रकार की गतिविधियों का आयोजन किया गया। इसके अलावा, दोनों देशों ने एक दूसरे की राजधानी में सांस्कृतिक केंद्र स्थापित किए। वर्ष 2011 में सियोल में, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद, भारत के तत्वाधान में स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र (एसवीसीसी) की स्थापना की गई थी। एक और सांस्कृतिक केंद्र 2013 में बुसान में, सरकारी-निजी भागीदारी रूपरेखा के जरिए स्थापित किया गया था। इसी समय, 2013 में, नई दिल्ली में कोरियाई सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना की गई। सांस्कृतिक केंद्र नियमित सांस्कृतिक प्रदर्शन, प्रदर्शनियों, व्याख्यान, सांस्कृतिक और भाषा शिक्षा एवं आउटरीच गतिविधियों समेत विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक आदान-प्रदान का केंद्र बिन्दु बन गए हैं।

वर्ष 2014 में कोरिया के राष्ट्रपति पार्क गुएन-हे की भारत यात्रा के दौरान, दोनों देशों ने सांस्कृतिक संपर्क को और बढ़ावा देने के लिए समझौते, आरओके- इंडिया कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम (2014-2017) पर हस्ताक्षर किए। राष्ट्रपति पार्क के दौरे के दौरान भारत सरकार ने कोरियाई नागरिकों के लिए वीजा-ऑन-अराइवल की सुविधा की भी घोषणा की। दोनों देशों के बीच कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए, 1994 के द्विपक्षीय नागरिक उड्डयन समझौते को नबंर 2015 में संशोधित किया गया, जिससे दोनों देशों के बीच साप्ताहिक उड़ानें बढ़कर 19 हो गईं; इसके परिणामस्वरूप कोरियन एयरलाइंस द्वारा नई उड़ानें शुरू की गईं, इससे नई दिल्ली और सियोल के बीच सीधी उड़ानें शुरू कीं। भारत और कोरिया के बीच उड़ानों की संख्या बढ़ाते और वीजा तंत्र में ढील देने से लोगों की कनेक्टिविटी में सुधार करने में मदद मिली है। वर्ष 2005 में भारत से कोरिया और कोरिया से भारत आने वाले लोगों की कुल संख्या लगभग 100,000 थी; 2019 में, यह 300,000 तक पहुंच गया। जबकि दोनों देशों के बीच यात्रा करने वाले लोगों की संख्या में वृद्धि हुई है, यह कोरिया और भारत आने वाले कुल विदेशियों के हिस्से के रूप में कम हो गया है या वही बना हुई है। (देखें- चित्र 3)।

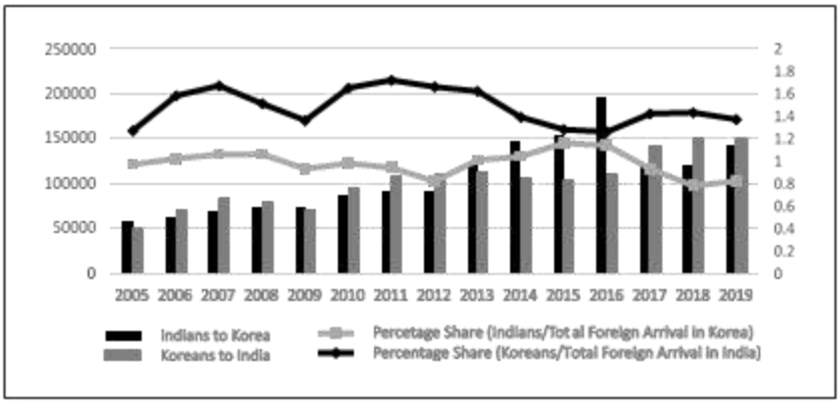

चित्र 3 लोगों के बीच आपसी आदान-प्रदान

(कोरियाई पर्यटन संगठन/ भारतीय पर्यटन मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट)

इस अवधि में दोनों देशों के अकादमिक और नीतिगत समुदायों को करीब लाने के लिए अनुसंधान संस्थानों, विचारक समूहों (थिंक टैंक) और विश्वविद्यालयों के बीच संस्थागत सहयोग का विस्तार भी देखा गया। इस

तरह की पहल में 2010 में विश्व मामलों की भारतीय परिषद और कोरिया के विदेश और राष्ट्रीय सुरक्षा संस्थान, भारत की विदेश सेवा संस्थान (एफएसआई) और कोरिया नेशनल डिप्लोमैटिक एकेडमी (केएनडीए) के बीच मार्च 2012 में हस्ताक्षर किए गए समझौता ज्ञापन शामिल हैं। भारत के मनोहर पर्रिकर इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस एंड स्ट्रैटेजिक एंड एनालिसिस (एमपी- आईडीएसए औक कोरिया के इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस एनालिसिस (केआईडीए) के बीच नियमित रक्षा और सुरक्षा संवाद भी नई दिल्ली और सियोल के बीच वैकल्पिक रूप से आयोजित किया गया है। वर्ष 2020 में, भारतीय वैश्विक परिषद और भारत के विकासशील देशों के लिए अनुसंधान और सूचना प्रणाली ने 2020 में कोरियन नेशनल डिप्लोमैटिक अकेडमी और कोरियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल इकॉनमिक पॉलिसी के साथ आर्थिक और विदेश नीति विचारक समूह की 2+2 वार्ता स्थापित करने के लिए टीम बनाई। इसके अलावा, कई भारतीय विश्वविद्यालयों ने भी संयुक्त अनुसंधान और छात्र एवं शिक्षक विनिमय के माध्यम से अकादमिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए कोरिया के कई विश्वविद्यालयों के साथ अनुबंध किया है। इस मामले में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली और दिल्ली विश्वविद्यालय ने पहल की है।

वर्ष 2015 में प्रधानमंत्री मोदी की कोरिया दौरे के बाद से, भारत और कोरिया के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत लिंक पर अधिक जोर दिया गया है। इस कदम ने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को भारतीय विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण एजेंडा बनाने के लिए मोदी सरकार के समग्र प्रयास को प्रतिबिंबित किया। इस संबंध में, दोनों देशों के बीच दो सहस्राब्दी पुराने वैवाहिक संबंध और दोनों देशों के बीच बौद्ध संबंधों के कोरियाई मिथक पर जोर दिया गया था। कोरिया में, यह माना जाता है कि अयोध्या से एक भारतीय राजकुमारी सुरीरत्ना (कोरिया में हियो ह्वांग-ओक के नाम से जानी जाती है), ने कोरिया का दौरा किया और एक कोरियाई राजा से शादी की। हालांकि, राजकुमारी की कहानी और उससे जुड़े सांस्कृतिक संबंध भारत में अभी तक अच्छी तरह से ज्ञात नहीं थे।

प्रधानमंत्री मोदी के दौरे के दौरान, यह घोषणा की गई थी कि अयोध्या के साथ कोरियाई लोगों के संबंधों को बढ़ाकर भारत और कोरिया अपने ऐतिहासिक संबंधों को मजबूत करेंगे। अयोध्या में रानी सुरीरत्ना के स्मारक को द्विपक्षीय परियोजना के रूप में अपग्रेड करने का भी निर्णय लिया गया। ऐतिहासिक जुड़ाव पर अकादमिक जुड़ाव को बढ़ावा देने के अलावा, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (आईसीसीआर) ने 2015 के सम्मेलन में रानी की कथा पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक प्रमुख अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया। राजनीतिक नेतृत्व द्वारा ऐतिहासिक संबंधों पर जोर देने से भारत-कोरिया संबंधों की दृश्यता में सुधार करने में मदद मिली। उदाहरण के लिए, 2018 में दीपोत्सव समारोह के अवसर पर प्रथम महिला मैडम मून की अयोध्या दौरे ने कई भारतीयों से अपील की, जो अन्यथा कोरिया या भारत- कोरिया संबंधों से परिचित नहीं हैं। उनके दौरे ने कोरियाई मिथक को लोकप्रिय बनाया और एक ऐतिहासिक तथ्य का दर्जा प्राप्त करने में मदद की। अपने दौरे के दौरान मैडम मून ने अयोध्या में राजकुमारी सुरीरत्ना के एक स्मारक की आधारशिला रखी जिसे दोनों देशों द्वारा संयुक्त रूप से बनाया गया था।

6. हिंद- प्रशांत और भारत-कोरिया संबंधों का भविष्य

जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, शीत युद्ध के बाद के दो दशकों में वैश्वीकरण, क्षेत्रीय एकीकरण और भू-राजनीतिक तनाव की अनुपस्थिति के दौरान एक अनुकूल अंतरराष्ट्रीय माहौल भारत- कोरिया के संबंधों के विकास का एक महत्वपूर्ण कारक था। हालांकि, वैश्विक राजनीति में भू-राजनीति की वापसी, जो मुख्य रूप से चीन के उदय, अमेरिका-चीन के रणनीतिक प्रतिस्पर्धा और देशों के बीच संबंधों के पुनर्निर्माण के संदर्भ में है,

एशिया में क्षेत्रीय माहौल को जटिल बना रहा है। बढ़ता राष्ट्रवाद और वि-वैश्वीकरण की बढ़ती प्रवृत्तियां शीत युद्ध के बाद की अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में बाधा पहुंचा रही हैं। हालांकि यह प्रक्रिया कुछ समय से चल रही है, हाल के वर्षों में अमेरिका में पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा और विशेष रूप से कोविड-19 महामारी के दौरान, इसकी गति तेज हुई है। हिन्द-प्रशांत का उदय एशिया में बदले रणनीतिक माहौल को दर्शाता है। हिन्द-प्रशांत का विचार और क्षेत्रीय व्यवस्था की पुनर्कल्पना, हालांकि इसे न तो शुरू किया गया था और न ही पूरी तरह से यह अमेरिका द्वारा संचालित था, मुख्य रूप से चीन को नियंत्रित करने के लिए अमेरिका के नेतृत्व वाली प्रक्रिया के रूप में बताया जाता है।[107] अमेरिका के साथ भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया समेत हिन्द-प्रशांत विचार के अन्य प्रवर्तकों के बीच आपस में बढ़ते संबंध और इन चार देशों के बीच संवाद (क्वाड) का क्रमिक विकास, जो बीजिंग के अनुसार, 'एशियाई नाटो' का रूप ग्रहण कर रहा है, अमेरिका-नीत भू-राजनीतिक परियोजना के रूप में हिन्द-प्रशांत के प्रमुख आख्यान को और अधिक सारगर्भित करता है। कोविड-19 के बाद की अवधि में अमेरिका-चीन प्रतिद्वंद्विता की गहनता के नई पर्यवेक्षकों को 'नए शीत युद्ध' के आगमन की घोषणा करने के लिए प्रेरित का है।[108]

हालांकि वाशिंगटन और अन्यों की तुलना में हिन्द-प्रशांत की भारत की अवधारणा में अंतर है, नई दिल्ली हिन्द-प्रशांत क्षेत्रीय निर्माण को बढ़ावा देने में सबसे आगे रही है। यह समुद्री एशिया के विकास को समझने और उसमें अपनी जगह तलाशने के लिए नई दिल्ली की रूपरेखा बन कर उभरा है। दूसरी ओर, कोरिया ने हिन्द-प्रशांत पर दुराव दिखाया है और इस संबंध में इसका नज़रिया भी अस्पष्ट रहा है।[109]

वर्ष 2018 में राष्ट्रपति मून जे-इन भारत के दौरे पर आए थे और इसी दौरान पहली बार भारत-कोरिया द्विपक्षी संदर्भ में हिन्द-प्रशांत पर दुविधा उभरी थी। दोनों पक्षों ने क्षेत्रीय व्यवस्था हेतु एक साझा दृष्टिकोण अपनाया और संयुक्त बयान में "शांतिपूर्ण, स्थिर, सुरक्षित, मुक्त, खुला, समावेशी और नियम-आधारित क्षेत्र" के प्रति प्रतिबद्धता जताई।[110] इसने "नौवहन की स्वतंत्रता, उड़ान भरने और अबाध वैध कारोबार... संवाद के माध्यम से विवादों का शांतिपूर्ण समाधान, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की केंद्रीयता" को अंतरराष्ट्रीय कानून के सार्वभौमिक रूप से मान्यता प्राप्त सिद्धांतों के अनुसार सुलझाए जाने के महत्व पर प्रकाश डाला।[111] हालांकि क्षेत्रीय व्यवस्था की साझा विज़न में हिन्द- प्रशांत के लिए इसका नज़रिया भारत के जैसा ही है, फिर भी यह 'हिन्द-प्रशांत' अवधारणा का समर्थन करने में विफल रहा है। संयुक्त बयान में यह भी कहा गया है कि, "कोरिया ने हिन्द-प्रशांत क्षेत्र के लिए भारत के समावेशी और सहयोगी विज़न पर ध्यान दिया"।[112] भले ही कोरिया भारत समेत हिन्द-प्रशांत के विचार को बढ़ावा देने वाले देशों के जैसे ही क्षेत्रीय व्यवस्था पर भी समान नज़रिया रखता हुआ प्रतीत होता है लेकिन हिन्द- प्रशांत के लिए इसका नज़रिया अस्पष्ट ही है।

हालांकि हिन्द-प्रशांत की अवधारणा लगभग एक दशक से अधिक पुरानी है, लेकिन 2017 में वाशिंगटन द्वारा "मुक्त और खुली हिन्द-प्रशांत रणनीति" की घोषणा किए जाने तक कोरिया में इस पर बहुत कम ध्यान दिया गया था। [113] कोरिया ने यह कहते हुए राष्ट्रपति ट्रम्प के हिन्द-प्रशांत रणनीति में शामिल होने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया था कि उसे इस प्रस्ताव से बहुत कम लाभ दिखाई दे रहा है।[114] हालांकि, हिन्द-प्रशांत के लिए कोरिया का रवैया पिछले तीन वर्षों में बदला है। कोरिया ने अपने क्षेत्रीय पहल के रूप में 'नई दक्षिणी नीति' की घोषणा की और अन्य देशों, जिनमें वे देश भी शामिल हैं जो सामान्य हितों के मुद्दों पर हिन्द-प्रशांत अवधारणा को बढ़ावा देते हैं, की क्षेत्रीय पहलों के साथ काम करने में दिलचस्पी दिखाई। इस संबंध में, सियोल ने नई दक्षिणी नीति और अमेरिका एवं ऑस्ट्रेलिया की हिन्द- प्रशांत पहल के बीच सामान्य आधार खोजने हेतु कदम उठाए थे। [115]

कोरिया ने 'हिन्द- प्रशांत पर आसियान का दृष्टिकोण/ आसियान आउटलुक ऑन द इंडो-पेसिफिक' (एओआईपी) का खुले तौर पर समर्थन किया और चीन- जापान- कोरिया त्रिपक्षीय सहयोग रूपरेखा के माध्यम से नई दक्षिणी नीति, चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और जापान के मुक्त और हिन्द-प्रशांत के बीच तालमेल बनाने का प्रस्ताव रखा।[116] इस विकास के बावजूद, सियोल ने हिन्द-प्रशांत अवधारणा पर अस्पष्टता बनाए रखी। इस अस्पष्टता को इसकी स्थिति की अभिव्यक्ति की अनुपस्थिति या अवधारणा के समर्थन के रूप में देखा जा सकता है। सियोल इस क्षेत्र को एशिया- प्रशांत के रूप में ही परिभाषित कर रहा है। हिन्द-प्रशांत की अवधारणा से दूरी बनाए रखने की कोरिया की कोशिश इस क्षेत्र में अमेरिका-नीत गौण वार्ता प्रारूपों जिसमें अन्यों के अलावा क्वाड और क्वाड प्लस एवं आर्थिक समृद्धि नेटवर्क, स्वच्छ नेटवर्क पहल भी है, के प्रति सजग दृष्टिकोण में भी दिखाई देती है।[117] हालांकि पहली नज़र में यह सतही और अर्थपूर्ण प्रतीत होता है, लेकिन कोरियाई परिप्रेक्ष्य में यह मामला गंभीर भू- राजनीतिक प्रभावों से भरा हुआ है। हिन्द- प्रशांत के प्रति कोरिया की रणनीतिक अस्पष्टता का नजरिया क्षेत्र में भू-राजनीतिक विकास के प्रति उसकी संवेदनशीलता को दर्शाता है। हालांकि कोरिया अमेरिका- आरओके गठबंधन को अपनी सुरक्षा के केंद्रबिन्दु के रूप में महत्व देता है, सियोल की दुविधा इस धारणा से उपजी है कि हिन्द-प्रशांत एक अमेरिकी नेतृत्व वाली भू-राजनीतिक दृष्टि है जिसे चीन को शामिल करने के लिए डिजाइन किया गया है।[118] हिन्द-प्रशांत में सियोल की अस्पष्टता अमेरिका और चीन के साथ अपने संबंधों के बीच एक नाजुक संतुलन बनाए रखने और दोनों के बीच रणनीतिक प्रतिस्पर्धा में उलझने से बचने की कोशिश करती है। चीन- अमेरिकी क्षेत्रीय प्रतिद्वंद्विता को तीव्र करने के संदर्भ में, कोरिया की क्षेत्रीय नीति के रूप में 'नई दक्षिणी नीति (एनएसपी)' का प्रचार, स्वायत्तता बनाए रखने और एक स्वतंत्र क्षेत्रीय अभिकर्ता के रूप में अपनी छवि को बेहतर करने का प्रयास है।[119] ऐसा करने में, सियोल बड़े सत्ता भू-राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के प्रभाव को कम करते हुए क्षेत्रीय अवसरों का लभा उठाने के लिए अमेरिका और चीन के बीच मध्यम मार्ग खोजने का प्रयास करता है। यह हिन्द- प्रशांत अवधारणा का समर्थन किए बिना चयनात्मक जुड़ाव की 'रणनीतिक अस्पष्टता' के अपने दृष्टिकोण को बनाए रखने में कोरिया को एक निश्चित मात्रा में लचीलापन भी प्रदान करता है।

क्षेत्रीय भू-राजनीतिक घटनाक्रम भारत-कोरिया संबंधों के आगे बढ़ने के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती पेश करते हैं क्योंकि दोनों देश दो अलग- अलग भू-राजनीतिक स्थानों से संबंधित हैं और क्षेत्रीय व्यवस्था के संवाद में अलग-अलग स्पर्शरेखा पर दिखाई देते हैं। हालांकि दोनों देश अपनी विदेश नीति के विकल्प बनाने में भू-राजनीति की बढ़ती विवशताओं का सामना कर रहे हैं, भारत क्षेत्रीय व्यवस्था के प्रति अपने दृष्टिकोण में सुरक्षा विचारों से प्रेरित प्रतीत होता है। दूसरी तरफ, कोरिया क्षेत्रीय सुरक्षा के मुद्दों को कम महत्व देता है और अपने क्षेत्रीय नज़रिए में आर्थिक एवं विकास संबंधी मुद्दों को प्राथमिकता देता है। भारत की विदेश नीति की यह विशेषता 2020 में भारत-चीन सीमा संघर्ष में और अधिक स्पष्ट हो गई है। भारत के हिन्द-प्रशांत नज़रिए की कोरियाई धारणा, जिसे अधिक सुलहकारी, हितधारकों और समावेश पर जोर देने के रूप में देखा गया है, भारत में चीन विरोधी भावना के उदय और अमेरिका के साथ नई दिल्ली के संबंधों को मजबूत बनाने के बाद बदला हुआ प्रतीत होता है। कोरिया के पर्यवेक्षकों ने कहा है कि भारत- चीन का जारी टकराव अमेरिका- भारत-चीन के बनते रणनीतिक त्रिकोण का हिस्सा है और नई दिल्ली को वाशिंगटन की ओर अधिक प्रेरित कर रहा है।[120]

जैसा कि चित्रित किया गया है, भारत- कोरिया संबंधों को आगे बढ़ाने के आख्यान को तैयार करने में भू-राजनीति एक प्रमुख कारक होगी। जिस गति से क्षेत्रीय विकास हो रहे हैं, उसे देखते हुए गलत धारणा की संभावनाएं अधिक हैं। वास्तविक चुनौती एक दूसरे के नजरिए और भावनाओं की सटीक समझ के जरिए धारणा और अपेक्षा के अंतर को सीमित करने का प्रबंध करना है। स्थिति दोनों देशों के बीच रणनीतिक संचार को

मजबूत करने का आहवान करती है। इस संबंध में, 2015 में स्थापित सचिव/ उप-मंत्री स्तर पर 2+2 वार्ता मंच बनाया गया था, अभी तक एक भी वार्ता आयोजित नहीं की गई है लेकिन यह बहुत महत्वपूर्ण है।

एक-दूसरे के क्षेत्रीय दृष्टिकोणों की कथात्मक रचना अलग-अलग लग सकती है हालांकि, वास्तव में भारत और कोरिया क्षेत्रीय व्यवस्था के अपने-अपने दृष्टिकोण में बहुत कुछ साझा करते हैं और समान चुनौतियों का सामना भी करते हैं। वर्ष 2018 का संयुक्त विज़न दस्तावेज स्पष्ट रूप से शांति और समृद्धि के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक खुले, नियम-आधारित और समावेशी क्षेत्र के साझा लक्ष्य को स्पष्ट करता है। ऐसे संदर्भ में जहां भारत और कोरिया अमेरिका-चीन महान शक्ति प्रतिद्वंद्विता की बढ़ती गहनता के दबावों को साझा करते हैं, नियम- आधारित व्यवस्था को मजबूत बनाने में निवेश करना उनके साझा हितों में है।

इस संबंध में, आसियान केंद्रीयता पर आधारित एक क्षेत्रीय व्यवस्था भारत और कोरिया के बीच संमिलन का बिन्दु है और एईपी और एनएसपी के लिए एक बैठक का आधार रहा है। नई दिल्ली और सियोल आसियान पर केंद्रित क्षेत्रीय संस्थानों में सक्रिए रूप से संलग्न हैं और बड़े सत्ता भू-राजनीतिक दबाव के दबाव का सामना करने के लिए आसियान की एकता और केंद्रीयता को सशक्त बनाने में उनकी साझा दिलचस्पी है। दोनों देशों ने आसियान में क्षमता निर्माण और कनेक्टिविटी परियोजनाओं में अपनी भागीदारी बढ़ा दी है। उनके अनुभव, विशेषज्ञता एवं क्षमताओं में संपूरकताओं को देखते हुए, भारत-कोरिया साझेदारी आसियान केंद्रित क्षेत्रीय एकीकरण प्रक्रिया के उनके साझा लक्ष्य को मूल्यवान बनाएगी।[121] भारत-कोरिया क्षेत्रीय साझेदारी का दायरा हिन्द माहासागर क्षेत्र समेत अन्य उप-क्षेत्रों तक भी बढ़ाया जा सकता है। कोरिया ने हिन्द महासागर क्षेत्र में गहरी दिलचस्पी दिखाई, जैसा कि 2018 में हिन्द महासागर रिम एसोसिएशन (आईओआरए) में एक क्षेत्रीय भागीदार के रूप में इसकी सदस्यता से संकेत मिलता है। प्रशांत द्वीप देशों में भारत-कोरिया के साथ तीसरे देश की साझेदारी भी तलाशना, एक उचित विचार है।

जैसे- जैसे क्षेत्रीय व्यवस्था की कथा अमेरिका और चीन पर अधिक केंद्रित होती जा रही है, विशेष रूप से दोनों के बीच रणनीतिक प्रतिद्वंद्विता, भारत और कोरिया जैसे मध्यम- शक्ति वाले देशों के लिए युद्धाभ्यास विवशता बनती जा रही है। जी2 के उद्भव के साथ, जहां बीजिंग और वाशिंगटन दोनों के बीच वैश्विक मामलों के प्रबंधन हेतु सामान आधार खोजने पर सहमत हुए है, यह भी सच है। हालांकि, ऐसी स्थिति की संभावना बहुत कम है लेकिन असंभव नहीं। दोनों अतिवाद भारत और कोरिया एवं इस क्षेत्र के अन्य मध्यम शक्तिसंपन्न देशों के लिए स्वीकार्य स्थिति नहीं है। नियम-आधारित क्षेत्रीय व्यवस्था के निर्माण की दिशा में व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से अपने प्रयासों को बढ़ाने के लिए मध्यम शक्ति वाले देशों की मांग बढ़ रही है।[122] ऐसी पहल संभावित रूप से संरचनात्मक संदर्भ को प्रभावित कर बड़े शक्तिसंपन्न राष्ट्रों के व्यवहार को अड़ियल बना सकते हैं। यह शक्तिसंपन्न राष्ट्रों से व्यवस्था-निर्माण के कुछ बोझ को भी कम कर सकता है। इस संबंध में, एशिया की तीसरी और चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने के नाते, कोरिया और भारत मध्यम शक्तिसंपन्न देशों का नेटवर्क तैयार करने की अच्छी स्थिति में हैं। इस संबंध में, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर दक्षिण पूर्व एशिया और ओशियानिया में संभावित साझीदारों के साथ त्रिपक्षीय/ गौण संवाद स्थापित करने की संभावनाओं का पता लगाने का सुझाव दिया गया है।

सहयोग का एक अन्य संभावित क्षेत्र है- बहुपक्षीय संगठनों में सहयोग। यह सुझाव दिया गया है कि आसियान के नेतृत्व वाली संस्थाओं जैसे ईस्ट एशिया समिट ईएएस आदि में सहयोग पर ध्यान दिया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संस्थानों पर केंद्रित संशोधित बहुपक्षवाद में सहयोग की भी संभावना है। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन, लीड आईटी, आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन और हिन्द महासागर क्षेत्र के लिए सूचना संधि केंद्र

(आईएफसी-आईओआर) जैसी भारत द्वारा शुरू की गई अंतरराष्ट्रीय पहलों में कोरिया की भागीदारी का भी सुझाव दिया गया है। नई भारत बहुपक्षीय पहलों द्वारा संबोधित मुद्दे भी एनएसपीपी ढांचे के तहत पहचाने गए एजेंडा हैं, विशेष रूप से इसके स्थायी शांति और सुरक्षा स्तंभ के तहत।

हिन्द-प्रशांत में भारत और कोरिया के बीच संभावित साझेदारी को कोरिया के एनएसपी प्लस 123 और भारत के हिन्द-प्रशांत सागर पहल (आईओपीआई) के बीच संमिलन हितों के माध्यम से और प्रगाढ़ किया जा सकता है। राष्ट्रपित मून ने नवंबर 2020 में आसियान- आरओके शिखर सम्मेलन में एनएसपी प्लस की घोषणा की थी। एनएसपी प्लस ने कोविड महामारी के संदर्भ में सियोल और आसियान की बदलती जरूरतों को प्रतिबिंबित किया। एनएसपी प्लस के सात प्रमुख स्तंभों ने बेहतर आर्थिक और स्वास्थ्य प्रणालियों के निर्माण और गैर-परंपरागत एवं मानव सुरक्षा चुनौतियों का समाधान करने पर ध्यान केंद्रित किया। एनएसपी प्लस का लोगों पर अधिक ध्यान है; यह स्वास्थ्य, शिक्षा और इंसानों पर महामारी के प्रभाव पर जोर देता है और इन चिंताओं को प्रस्तावित पुनर्प्राप्ति प्रयासों के केंद्र में रखता है। दूसरी तरफ, आईओपीआई की घोषणा नवंबर 2019 में भारत की हिन्द-प्रशांत विज़न को आगे ले जाने के लिए की गई थी। यह सात विषयगत क्षेत्रों- क) समुद्री सुरक्षा, ख) समुद्री पारिस्थितिकी, ग) समुद्री संसाधन, घ) क्षमता निर्माण और संसाधन साझा करना, ड) आपदा जोखिम को कम करना और उसका प्रबंधन, च) विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं अकादमिक सहयोग, और छ) व्यापार, कनेक्टिविटी एवं समुद्री परिवहन, में व्यावहारिक सहयोग के माध्मम से, विशेष रूप से समुद्री क्षेत्र में चुनौतियों को कम करने के लिए खुली, समावेशी, गैर - संधि- आधारित पहल है। भारत एकतरफा पहल और द्विपक्षीय, बहुपक्षीय एवं लघुपक्षीय सहयोग के माध्यम से अपनी हिन्द-प्रशांत विज़न को बढ़ावा देने को प्रतिबद्ध है।

स्वास्थ्य और आर्थिक संकट पैदा करने वाली कोविड-19 महामारी ने भारत-कोरिया संबंधों के लिए एक नया संदर्भ पैदा किया है। व्यवधान के बावजूद, महामारी के बाद के विकास ने नए द्विपक्षीय सहयोग के अवसर पैदा किए हैं क्योंकि दोनों देश अपनी राष्ट्रीय विकास नीति, भारत को अपनी आत्मनिर्भर भारत पहल और कोरिया की न्यू डील पॉलिसी के माध्यम से फिर से प्राथमिकता दे रहे हैं। नए और उभरते क्षेत्रों में अवसरों का लाभ उठाने के लिए क्षेत्रीय संवाद स्थापित करने का सुझाव दिया गया है। जैसे, डिजिटल प्रौद्योगिकी, समुद्री सुरक्षा, हरित प्रौद्योगिकी, विश्वसनीय और लचीली आपूर्ति श्रृंखलाओं पर भारत- कोरिया संवाद तंत्र स्थापित करने की अत्यधिक अनुशंसा की जाती है।

रक्षा साझेदारी भारत- कोरिया विशेष रणनीतिक साझेदारी के एक महत्वपूर्ण स्तंभ के रूप में उभरी है। रक्षा औद्योगिक सहयोग के महत्व को स्वीकार करते हुए, दोनों देशों के बीच अपेक्षाओं के अंतर को पाटना महत्वपूर्ण है। भारत और कोरिया के साथ लंबी अवधि में 'रक्षा स्वायत्तता' की मांग के उद्देश्य को साझा करने के साथ, दोनों देशों के पास विभिन्न हथियार प्रणालियों के डिजाइन, विकास और अनुसंधान एवं विकास हेतु संयुक्त उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करने वाली रक्षा साझेदारी के वर्तमान चरण से आगे बढ़ने के लिए अधिक प्रोत्साहन हैं। एक बड़ी लागत वाली संयुक्त रक्षा परियोजना निरपवाद रूप से भारत-कोरिया रणनीतिक साझेदारी की रूपरेखा को बढ़ाएगी।

ऐसे में जबकि भारत-कोरिया आर्थिक संबंध मजबूत स्थित में हैं, बढ़ते द्विपक्षीय व्यापार घाटे की प्रवृत्ति और कोरिया को भारतीय निर्यात में ठहराव भारतीय पक्ष के लिए चिंता का विषय है। यह देखते हुए कि यह एक संरचनात्मक मुद्दा है जिसे आसानी से हल करना मुश्किल है, इस मुद्दे को एक अलग मानसिकता के साथ देखना महत्वपूर्ण है ताकि इसे ऐसा मुद्दा न बनाया जाए जो रिश्ते के समग्र आख्यान को तोड़ सके। इस संबंध में, यह सुझाव दिया गया है कि भारत को व्यापार घाटे वाले देश की तुलना में भारत के विनिर्माण और निर्यात

को बढ़ाने की क्षमता वाले एक महत्वपूर्ण भागीदार के रूप में कोरिया को पहचानने की आवश्यकता है। कोरिया को यह मानना चाहिए कि भारत 10 वर्षों में जी3 देश बन जाएगा। इस प्रकार का नज़रिया रखने से भारत-कोरिया सीईपीए पुनःवार्ता अधिक अनुकूल और सहायक हो जाएगी।

संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए एक अन्य प्रमुख स्तंभ जिस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है, वह है, लोगों के बीच संपर्क, जिसे सशक्त भौतिक, सांस्कृतिक और संस्थागत कनेक्टिविटी के माध्यम से बढ़ावा दिए जाने की आवश्यकता है। इससे न केवल दोनों देशों के बीच सोशल नेटवर्किंग का विस्तार करने में मदद मिलेगी बल्कि कोरिया के लोगों में भारत के बारे में और भारत के लोगों में कोरिया के बारे में जागरूकता भी बढ़ेगी।

यह देखते हुए कि हिन्द-प्रशांत इतिहास और क्षेत्रीय संस्थागत रूपरेखा अभी भी विकसित हो रहा है, यह महत्वपूर्ण है कि नई दिल्ली और सियोल को क्षेत्रीय सहयोग के लिए खुला दिमाग रखना चाहिए। जैसे, क्वाड स्वयं एक राजनीतिक- सुरक्षा संवाद तंत्र से एक व्यापक-आधार वाले मंच के रूप में विकसित हुआ है जिसमें कोविड महामारी, स्वास्थ्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन, बुनियादी ढांचे और आपूर्ति श्रृंखला पर सहयोग समेत अन्य मुद्दों पर चर्चा की गई है। इस संबंध में, नई दिल्ली विकसित हो रहे हिन्द- प्रशांत बहु और गौण मंचों पर कोरिया की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए पहल करेगी।

मार्च 2022 में हाल ही में हुए राष्ट्रपति चुनाव में यून सुक-योल की जीत के साथ प्रगतिवादियों से रूढ़िवादियों में राजनीतिक परिवर्तन, यह भविष्य में कोरिया के हिन्द-प्रशांत के नजरिए में एक महत्वपूर्ण बदलाव देखने की संभावना है। यून अंतर-कोरियाई संबंधों और अमेरिका एवं चीन के बीच संतुलन पर अधिक जोर देने के लिए मून की विदेश नीति के आलोचक रहे हैं, जो उनके अनुसार, परिणामस्वरूप बीजिंग का तुष्टीकरण हुआ और अमेरिका-कोरिया गठबंधन कमजोर हुआ। 'प्रेडिक्टेबल डिप्लोमेसी' के बैनल तले, यून ने अमेरिका-कोरिया सुरक्षा गठबंधन के मजबूत करके कोरिया की स्थिति को 'निर्णायक वैश्विक सत्ता' के रूप में बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है, आपसी सम्मान पर आधारित एक सैद्धांतिक चीन नीति, हिन्द-प्रशांत के लिए एक प्रेरित दृष्टिकोण है। यदि राष्ट्रपति चुनाव यून, जब वह मई 2022 में पदभार ग्रहण करते हैं, तो कोरियाई विदेश नीति में बदलाव ला सकते हैं, जैसा कि उन्होंने अपने चुनाव अभियान के दौरान निर्धारित किया था, कोरिया के साथ हिन्द-प्रशांत में अपनी वर्तमान अस्पष्टता से दूर जाकर एक सक्रिए भूमिका निभा रहा है। भारत-कोरिया संबंधों में सुधार हेतु नया मार्ग प्रशस्त करेगा।

7. निष्कर्ष

रणनीतिक साझेदारी प्रतिमान के तहत भारत-कोरिया संबंध व्यापक और बहुआयामी हो गए हैं। द्विपक्षीय कारकों जिसमें भारत में मजबूत आर्थिक विकास और तकनीकी महाशक्ति के रूप कोरिया का उदय, दोनों अर्थव्यवस्थाओं के बीच आर्थिक पूरकताएं और वैश्वीकरण और क्षेत्रीय एकीकरण की विशेषता वाले शीत युद्ध के बाद के अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था शामिल हैं, ने, दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को बनाने में मदद की।

इसकी लोकप्रियता के बावजूद, रणनीतिक साझेदारी का अर्थ अस्पष्ट बना हुआ है।[124] शीत युद्ध के बाद की अवधि में उभरी एक अवधारणा के रूप में, रणनीतिक साझेदारी 21वीं सदी में द्विपक्षीयता के एक नए रूप का प्रतिनिधित्व करती है, जो इसे शीत युद्ध युग के द्विपक्षीय संबंधों से अलग करती है, जो मुख्य रूप से अन्नय, खतरे से प्रेरित और मित्रों एवं शत्रुओं के द्विआधारी भाषा में तैयार किए गए थे। [125] एक रणनीतिक साझेदारी को 'साझेदारी कूटनीति' पर केंद्रित विशेषाधिकार प्राप्त द्विपक्षीय संबंधों के रूप में समझा जा सकता है जो देश उन मुद्दों पर काम करने को प्राथमिकता देते हैं जहां वे एक सुसंगत और समन्वित पारस्परिक हित

पाते हैं। यह राष्ट्रों को अन्य साझेदारों के साथ अलग-अलग हितों को आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त लचीलापन और कौशल के लिए स्थान बनाता है।[126] शीत युद्ध की अवधि के विपरीत, जिसके दौरान 'रणनीतिक' अवधारणा सैन्य सुरक्षा के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई थी, रणनीतिक साझेदारी रूपरेखा के तहत आर्थिक, विकास, प्रौद्योगिकी और गैर-परंपरागत सुरक्षा मुद्दों को शामिल करने के लिए रणनीतिक विचारों का विस्तार हुआ है।

द्विपक्षीय संबंधों के एक नए रूप में रणनीतिक साझेदारी के परिप्रेक्ष्य में तीन महत्वपूर्ण विशेषताओं, जिनका भारत-कोरिया संबंधों के लिए क्या अर्थ है, की पहचान की जा सकती है। सबसे पहला, रणनीतिक साझेदारी रूपरेखा ने भारत- कोरिया संबंधों का एक नया आख्यान प्रदान किया, एक दूसरे की विदेश नीति में इसकी विशेषाधिकार प्राप्त स्थिति को उजागर किया। यह अंतरराष्ट्रीय समुदाय में भारत और कोरिया की बेहतर हुई स्थिति की स्वीकृति और उनके संबंधित रणनीतिक दृष्टिकोण में एक दूसरे की बढ़ती प्राथमिकता का भी संकेत था। इस प्रकार 'रणनीतिक साझेदारी' के संबंध की स्थिति के उत्थान ने भारत-कोरिया द्विपक्षीय संबंधों में एक नई सीमा को चिन्हित किया।

रणनीतिक साझेदारी प्रतिमान के तहत भारत-कोरिया संबंधों से जुड़ी दूसरी विशेषता द्विपक्षीय संबंधों के संस्थागतकरण में महत्वपूर्ण प्रगति रही है। विदेश और सुरक्षा नीति, रक्षा, ऊर्जा, साइबर सुरक्षा, व्यापार, निवेश, विज्ञान और प्रौद्योगिकी समेत कई नीतिगत क्षेत्रों में विभिन्न स्तरों पर संरचित संवाद तंत्र स्थापित करने के संबंध को संस्थागतकरण परिलक्षित हुआ है। विभिन्न सरकारी एजेंसियों के बीच स्थापित संरचित संवाद तंत्र न केवल किसी विशेष क्षेत्र में हितों को आगे बढ़ाने के लिए नियमित संचार हेतु मार्ग प्रदान करता है बल्कि कुछ क्षेत्रों में मतभेद होने पर भी संबंधों में निश्चित गति बनाए रखने में मदद करता है।

तीसरी विशेषता रणनीतिक साझेदारी के संवैधानिक पहलुओं से जुड़ी कई व्याख्याएं हैं। दूसरे शब्दों में, भारत-कोरिया संबंधों को रणनीतिक बनाने के लिए कई स्पष्टीकरण मौजूद हैं। पहला सरंचनात्मक आख्यान है जो भारत-कोरिया संबंधों को विकसित भू- राजनीतिक संदर्भ में इस दृष्टिकोण के साथ स्थापित करता है कि संबंधों में विकास एक दूसरे की बाहरी संतुलन या हेजिंग रणनीति का हिस्सा है। संबंधों का आर्थिक आयाम रणनीतिक साझेदारी के अर्थ की दूसरी व्याख्या का केंद्र है। ऐसा परिप्रेक्ष्य आर्थिक परिवर्तन को एक रणनीतिक उद्देश्य बताता है और उस लक्ष्य को प्राप्त करने में एक आवश्यक कारक के रूप में भारत-कोरिया संबंधों पर प्रकाश डालता है। भारत में कई पर्यवेक्षकों का यह मानना है कि कोरिया पूंजी और प्रौद्योगिकी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है जो भारत के आर्थिक परिवर्तन में योगदान दे सकता है। इसके विपरीत, कोरिया भारत के साथ अपनी आर्थिक साझेदारी को मजबूत करने को आर्थिक विकास के नए स्रोत और महान शक्तियों, विशेष रूप से चीन पर अपनी आर्थिक और कूटनीतिक निर्भरता में विवधता लाने के अवसर के रूप में देखता है। नई दिल्ली और सियोल के बीच बढ़ती रक्षा और सुरक्षा साझेदारी, विशेष रूप से रक्षा औद्योगिक सहयोग ने, रक्षा आपूर्तिकर्ताओं के विविधीकरण और आत्मनिर्भरता के माध्यम से रणनीतिक स्वायत्तता प्राप्त करने के भारतीय और कोरियाई लक्ष्य को देखते हुए महत्वपूर्ण रणनीतिक मूल्य हासिल कर लिया है।

उच्च स्तर के लचीलेपन को देखते हुए, एक रणनीतिक साझेदारी अंतरराष्ट्रीय माहौल में परिवर्तन के लिए बहुत अधिक उत्तरदायी और अनुकूल है, यह इसे अंतरराष्ट्रीय माहौल एवं साझीदारों की तुलना में अनिश्चितता के खिलाफ बचाव हेतु आदर्श साधन बनाती है। इसका अर्थ यह भी है कि रणनीतिक साझेदारी से जुड़ा अर्थ संरचनात्मक और द्विपक्षीय स्थितियों पर निर्भर है। भारत-कोरिया संबंध कोई अपवाद नहीं है। चूंकि संरचनात्मक और द्विपक्षीय संदर्भ जिसमें भारत-कोरिया संबंध विकसित हुए हैं, हिन्द-प्रशांत अंतरराष्ट्रीय

व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है और दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी की प्रकृति, दायरा और अर्थ भी।